राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

# स्वतंत्र प्रभात

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें........ 9511151254



@swatantraprabhatmedia | @swatantramedia | RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) | @SwatantraPrabhatonline | news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर,बुधवार, 24 जून 2026

वर्ष 14,अंक 75, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया

www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित



राम मंदिर चढ़ावा विवादः हाई कोर्ट ने जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार...03

कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन को तुरंत खत्म करने का आदेश, दिल्ली पुलिस ने फाउंडर अभिजीत को भेजा नोटिस...04


## रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला, 2.70 लाख निर्माण श्रमिकों को मिलेगा कैशलेस इलाज

दिल्ली सरकार ने राजधानी के श्रमिकों व उनके परिवारों के स्वास्थ्य को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने राजधानी के पंजीकृत भवन निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए दिल्ली भवन निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य योजना को स्वीकृति प्रदान की है, इस योजना से दिल्ली के लगभग 2.70 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों सहित करीब 10 लाख लोगों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा, इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों और उनके परिवार का वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण तो कराया जाएगा ही, साथ ही कई चिकित्सीय सुविधाएं भी निशुल्क मिलेंगी. उपचार की पूरी प्रक्रिया कैशलेस होगी, जिससे श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ेगा.

### कैबिनेट ने स्वास्थ्य योजना को दी मंजूरी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेष रूप से गरीब, श्रमिक और वंचित परिवारों के कल्याण के लिए पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है.निर्माण श्रमिक राजधानी के विकास की नींव हैं. उनके स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है. इसी उद्देश्य से कैबिनेट ने इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना को मंजूरी दी है. उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों से जुड़े श्रमिकों को अपने कार्य के दौरान पत्थरों को काटने से निकली धूल, रसायनों, अत्यधिक शोर, भारी मशीनों, सामान्य धूल और कठिन श्रम जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है. इसके कारण उन्हें सिलिकोसिस (फेफड़ों की बीमारी), श्वसन संबंधी रोग, त्वचा रोग और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बना रहता है. लंबे समय से इस वर्ग के लिए किसी व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का अभाव था, जिसे ध्यान में रखते हुए यह योजना तैयार की गई है.मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों तथा उनके पात्र परिवारजनों, जिनमें पति या पत्नी, बच्चे और माता-पिता शामिल हैं, को सूचीबद्ध अस्पतालों और मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों के माध्यम से निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक को सूचीबद्ध अस्पतालों में दो लाख रुपये तक के उपचार की सुविधा मिलेगी, जबकि एक परिवार के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये तक होगी. उपचार की पूरी प्रक्रिया कैशलेस होगी, जिससे श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ेगा.

### पंजीकृत श्रमिकों को मिलेंगी ये सुविधाएं

इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों और उनके जीवनसाथियों का वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाएगा. इसके अतिरिक्त निःशुल्क OPD और IPD सेवाएं, जांच एवं प्रयोगशाला सुविधाएं, आपातकालीन चिकित्सा सहायता, रेफरल सेवाएं तथा निर्माण स्थलों और श्रमिक बहुल क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. मुख्यमंत्री के अनुसार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड तैयार किए जाएंगे और एक आधुनिक लाभार्थी ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की जाएगी, जिससे सेवाओं की निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके. इसके अलावा श्रमिकों की सहायता के लिए 24म7 टोल-फ्री हेल्पलाइन भी संचालित की जाएगी.

### श्रमिकों और उनके परिवार का जीवन बेहतर बनाने पर फोकस

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह योजना केवल स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि श्रमिकों और उनके परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा पहल है. सरकार इस योजना पर प्रतिवर्ष लगभग 200 करोड़ रुपये व्यय होने की संभावना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने भी गरीबों, श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. आयुष्मान भारत, ई-श्रम पोर्टल, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से श्रमिक वर्ग को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के निरंतर प्रयास किए गए हैं. दिल्ली सरकार भी उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है.

## फायर NOC नहीं, एग्जिट नहीं... दिल्ली के कोचिंग सेंटरों में बच्चों की जान से खिलवाड़!

यूपी की राजधानी लखनऊ के अलीगंज स्थित एक एनीमेशन सेंटर (गेमिंग और एनिमेशन कोचिंग) में सोमवार को भीषण आग लगने की दर्दनाक घटना सामने आई, जिसमें 15 बच्चों की जान चली गई. हादसे की जांच के लिए सीएम योगी ने SIT जांच का गठन किया है. शुरुआती जांच में पता चला कि इस एनीमेशन सेंटर में भी फायर के तमाम नियम-कानून का उल्लंघन किया जा रहा था. वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी कोचिंग सेंटर में आग लगने के कई बड़े मामले पहले हो चुके हैं, जिनमें कई लोगों की जान जा चुकी है. इन कोचिंग सेंटर्स के संचालक बिना फायर NOC के फायर के नियमों को ताक पर रख कर यह कोचिंग सेंटर चलाते हैं. अगर कोई हादसा होता है तो इनमें मरने वालों की संख्या काफी ज्यादा हो जाती है. लखनऊ हादसे के बाद शकरपुर में खुले बिजली के तारों का जाल है. उन्हीं से सटे हुए कोचिंग सेंटर चल रहे हैं. कोचिंग सेंटर में जाने की करीब डेढ़ से 2 फीट की सकरी एक सीढ़ी होती है. एंट्री और एग्जिट के लिए बस यही एक सीढ़ी होती है और ऊपर पहुंचने पर कमरों में भी किसी भी तरह की कोई एग्जिट नहीं होता. यानी अगर किसी हादसे की वजह से आग लगती है तो लोग कोचिंग सेंटर में फंसे रह जाएंगे.

### छोटे-छोटे केबिन बनाकर बच्चों को बैठाया जाता

ऐसा ही एक और कोचिंग सेंटर है, जो काफी बड़ा है. कोचिंग सेंटर में ऊपर जाने के लिए एक संकरी सीढ़ी है. एग्जिट के लिए भी इसी सीढ़ी का इस्तेमाल होता है. ऊपर अलग-अलग छोटे-छोटे केबिन बनाए गए हैं, जिनमें बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं. इनमें कई AC लगे हुए हैं. कोचिंग सेंटर के पीछे की तरफ बालकनी में लोहे की जाली लगी है. दूसरी तरफ भी गेट लगा हुआ है. यानी अगर आग लगती है तो कोई भी न तो पीछे की तरफ से और न ही आगे की तरफ से बाहर निकल सकता है या ऊपरी मंजिल से कूद कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर सकता है, बल्कि उसी में फंसा होकर रह जाएगा और आग से या दम घुटने से उसकी मौत हो सकती है. एक दो कोचिंग सेंटर में फायर एक्सटिंग्विशर हैं, लेकिन वह एक्सपायर हो चुके हैं. इसके अलावा कई कोचिंग सेंटर ऐसे हैं, जिनमें बायोमेट्रिक लॉक लगा हुआ है. यानी शॉर्ट सर्किट होने पर यह दरवाजे अपने आप लॉक हो जाएंगे और अंदर के लोग अंदर ही फंसे रह जाएंगे. वह बाहर नहीं निकाल पाएंगे. हादसे के सूरत में मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है.

### सिर्फ डेढ़ फीट चौड़ी सीढ़ियों से आते-जाते हैं बच्चे

लक्ष्मी नगर में ऐसी ही एक और लाइब्रेरी है, जो करीब डेढ़ फीट चौड़ी सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाती है. अंदर बायोमेट्रिक लगा हुआ है. लाइब्रेरी संचालक ने कबूल किया कि उनके पास फायर की NOC नहीं है. बताया कि यहां किसी भी कोचिंग सेंटर के पास फायर NOC नहीं है. इस लाइब्रेरी में भी‹ष्ट लगे हैं. निकालने के लिए कोई भी जगह नहीं है. यानी बच्चों की जिंदगी के साथ यह कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी वाले खिलवाड़ कर रहे हैं. 3 जून को दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के हौजरानी में एक होटल में आग लग गई थी, जिसमें 24 लोगों की मौत हो गई, जिसमें ज्यादातर विदेशी लोग थे. इस होटल के पास भी फायर NOC नहीं थी. नियमों के विपरीत बेसमेंट बनाया गया था और एंट्री और एग्जिट का सिर्फ एक रास्ता था. शॉर्ट सर्किट के बाद जब आग लगी तो बायोमेट्रिक गेट होने की वजह से दरवाजे लॉक हो गए और लोग अंदर ही फंसे रह गए, जिससे आग में जलकर और दम घुटने से 24 लोगों की मौत हो गई.

### 24 मौतों का जिम्मेदार कौन?

ऐसे हादसों के बाद प्रशासन थोड़े समय के लिए दिखावा करते हुए हरकत में आता है. होटल के मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार किया गया, उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया. कुल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर 24 मौतों की जिम्मेदारी उनके ऊपर थोपी गई. इस वक्त वह तीनों जेल में हैं. थोड़े समय में जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन सवाल यह उठता है कि 24 मौत का असली जिम्मेदार कौन है? प्रशासन ने मालवीय नगर इलाके के कुछ होटल को सील किया, जो नियमों का पालन नहीं कर रहे थे. इन होटल के दरवाजे पर एमसीडी ने सील लगाई है, लेकिन दिल्ली में अभी भी लाखों कोचिंग सेंटर और होटल बिना फायर NOC और बिना फायर के नियमों का पालन करते हुए चला जा रहे हैं. लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं.

## संक्षिप्त ख़बरें

### मैनपुरी से नए कैंटर का पूजन कराने लाए थे बटेश्वर, नहाते समय यमुना के गहरे पानी में डूबा युवक; मौत

**बटेश्वर (आगरा)।** मैनपुरी में खरीदे गए नए कैंटर का पूजन कराने के लिए कुछ लोग सोमवार को बटेश्वर पहुंचे। यहां पूजन के बाद कैंटर स्वामी के साथ आया युवक, यमुना में स्नान के लिए चला गया। नहाते-नहाते वह गहरे पानी में डूब गया। वहीं युवक की मां का रो-रोकर बुरा हाल है। मैनपुरी जनपद के थाना औंछा क्षेत्र के पिडरिया चौराहा गांव दलीपुर निवासी विकास (25) पुत्र सुरेश अपनी मां हरिप्यारी के साथ गांव के ही संजीव की कैंटर गाड़ी का पूजन कराने बटेश्वर आया था। मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद विकास महादेव घाट पर दोपहर करीब दो बजे करीब स्नान करने लगा। इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया तो घाट पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर बटेश्वर पुलिस मौके पर पहुंच गई और गोताखोरों को बुलाकर तलाश अभियान शुरू कराया। मां हरिप्यारी का रो-रोकर बुरा हाल है। करीब तीन घंटे बाद गोताखोरों ने उसके शव को बाहर निकाल लिया।

### दूल्हे ने शराब पीकर किया ड्रामा, अलीगढ़ में शादी के बाद दुल्हन ने किया साथ जाने से इनकार

**विजयगढ़ (अलीगढ़)।** शादी के मंडप में फेरे लेने के बाद विदाई से पहले दूल्हे द्वारा शराब पीने की बात उजागर होने पर विवाद पनप गया जिससे दुल्हन का दिल टूट गया, जहां परिवार शादी की खुशियां मना रहा था, तो सभी रिश्तेदार विदाई का इंतजार कर रहे थे, वहां कुछ ही देर में सन्नाटा पसर गया। दुल्हन ने दूल्हे के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया, मामला स्थानीय थाने में पहुंचा लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं हो सका जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के ग्राम नगला बरी निवासी जगबीर सिंह ने अपनी बेटी का रिश्ता बिचौलियों के माध्यम से ग्राम नागवाई जिला एटा निवासी नेम सिंह के पुत्र सचिन के साथ किया था। शादी की दोनों ओर से धूमधाम के साथ तैयारियां की गई थीं बताते हैं।

## अवैध हिरासत मामला: UP सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 10 लाख के मुआवजे पर लगाई रोक

- सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश पुलिस की गिरफ्तारी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं. राज्य सरकार के वकील ने आज अदालत को बताया कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के लिखित आधार नहीं दिए गए थे, जिसकी उन्होंने पुष्टि कर दी

हालांकि, सरकार ने केवल लगाए गए जुर्माने की राशि पर आपत्ति जताई

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट के इस निष्कर्ष पर कोई विवाद नहीं है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए थे. वकील ने कोर्ट से कहा कि मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए थे। मैं केवल लगाए गए जुर्माने की राशि के बारे में बात कर रहा हूं. संबंधित साह्न को हमने सस्पेंड कर दिया था. इसके बाद कोर्ट ने हिरासत में लिए गए व्यक्ति को मुआवजा देने के आदेश पर रोक लगा दी।

### उत्तर प्रदेश पुलिस की गिरफ्तारी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए

ये मामला मनोज कुमार द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका से जुड़ा है. उन्होंने उन्नाव में दर्ज एक आपराधिक मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और हिरासत से रिहाई की मांग की थी।

### जनवरी में किया गया था गिरफ्तार

कुमार को सितंबर 2024 में दर्ज FIR के सिलसिले में 27 जनवरी, 2026 को गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने तर्क दिया कि गिरफ्तारी गैर-कानूनी थी क्योंकि पुलिस उन्हें गिरफ्तारी के लिखित आधार देने में विफल रही, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) की व्याख्या करने वाले सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों में अनिवार्य किया गया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाया कि मनोज कुमार की गिरफ्तारी मेमो में सिर्फ केस नंबर लिखा था, गिरफ्तारी की कोई वजह नहीं बताई गई थी. कोर्ट ने कहा कि वजह न बताने से पूरी गिरफ्तारी और रिमांड गैर-कानूनी हो गई. कोर्ट ने राज्य सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (होम) से पूछा कि कुमार को तीन महीने तक गलत तरीके से जेल में रखने के लिए सरकार पर भारी जुर्माना क्यों न लगाया जाए. कोर्ट ने यह भी कहा कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने कोर्ट के आदेश को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि सिर्फ औपचारिक जवाब दिया.

कोर्ट ने कहा, 'अगर होम डिपार्टमेंट के सबसे बड़े अधिकारी, यानी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (होम) की तरफ से दिमाग का इस्तेमाल न करने का ऐसा मामला सामने आता है, तो हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि राज्य के दूसरे अधिकारी कैसे काम कर रहे होंगे।

## एकल आवास का नक्शा पास और वीपी शुक्ला ने खड़ी कर दी चार मंजिला इमारत, घोर अराजकता

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**लखनऊ।** राजधानी लखनऊ के अब तक के सबसे बड़े अग्निकांड में जिला और पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है। बिजली विभाग के साथ ही एलडीए और नगर निगम भी कठघरे में हैं। अलीगंज के पुरनिया/सेक्टर डी इलाके में जिस भवन में आग लगी और 18 लोगों की मौत हुई है, उसका सिर्फ भूतल का आवासीय नक्शा पास था और चार मंजिला व्यावसायिक भवन खड़ा कर दिया गया। इस बिल्डिंग को फायर और विद्युत सुरक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं मिला था।

इसके बाद भी वीरेन्द्र प्रसाद शुक्ला पुत्र सुरेंद्र प्रसाद शुक्ला अलीगंज पेट शॉप और गेमिंग जोन के साथ अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित कर रहे थे। इसमें इंट्री और एक्जिट भी एक ही है। इसके बाद भी किसी सरकारी मुलाजिम की नजर इधर नहीं पड़ी। इनके मकान पर विद्युत लोड 20 किलोवाट का पास था और यह लोग 35.50 किलोवाट का उपयोग कर रहे थे।

### लाइसेंस कैसे मिला

बिल्डिंग पर फायर की एनओसी और बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं था, इसके बाद भी यहां गतिविधियां संचालित थीं। फरवरी 2025 में अलीगंज समेत कई संस्थानों पर नोटिस जारी होने और लाइसेंस रद करने की सिफारिश की गई थी। इसके बाद भी भीषण गर्मी में इस बिल्डिंग में आधा दर्जन से अधिक एसी चल रहे थे।


### लाइसेंस कैसे मिला

बिल्डिंग पर फायर की एनओसी और बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं था, इसके बाद भी यहां गतिविधियां संचालित थीं। फरवरी 2025 में अलीगंज समेत कई संस्थानों पर नोटिस जारी होने और लाइसेंस रद करने की सिफारिश की गई थी। इसके बाद भी भीषण गर्मी में इस बिल्डिंग में आधा दर्जन से अधिक एसी चल रहे थे।


## केन्या से स्टडी वीजा पर दिल्ली आकर बेच रहे थे ड्रग्स, पुलिस ने नाइजीरियाई साथी समेत 3 तस्करों को दबोचा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**पूर्वी दिल्ली।** डेढ़ साल पहले केन्या से एक युवक पीएचडी करने के लिए दिल्ली आया। एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर पढ़ाई करने लगा। इस दौरान तस्करों के साथ मिलकर ड्रग्स की तस्करी करने लगा। प्रीत विहार थाना पुलिस ने कन्या के छात्र समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान राधू पैलेस झुग्गी निवासी आफताब, केन्या छात्र अबोंगो केनेडी और नाइजीरियाई नागरिक लकी के रूप में हुई है। इनके पास से 61 ग्राम गांजा, 11 ग्राम एमडीएमए, दो स्कूटी व तस्करी से कमाए गए 1.37 लाख रुपये बरामद किए हैं। जिला पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि विकास मार्ग के पास एक युवक ड्रग्स लेने आने वाला है थानाध्यक्ष सुबोध कुमार सोलंकी के नेतृत्व में एसआई क्रांतिवीर, कांस्टेबल अनुभव की एक टीम बनाई।

### क्यूबा कैफे के पास जाल बिछाकर पकड़ा

टीम ने क्यूबा नाम के एक कैफे के पास अपना जाल बिछाया। एक स्कूटी सवार संदिग्ध वहां पर पहुंचा। पुलिस ने उसे दबोच लिया। आरोपित की पहचान आफताब के रूप में हुई। इसके पास से पुलिस ने एमडीएमए ड्रग्स बरामद की। इसने बताया कि वह नाइजीरिया के नागरिक से ड्रग्स खरीदता है। आरोपित की निशानदेही पर पुलिस ने गणेश नगर से इसके दो विदेशी साथी को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि केन्या का नागरिक पढ़ाई की वीजा पर भारत आया था। जबकि नाइजीरिया नागरिक का पोस्टमार्ट व अन्य कागजात मिले नहीं हैं। नाइजीरिया का नागरिक तस्करों के संपर्क में था। यह ड्रग्स लेकर दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में बेचता था। केन्या का छात्र उसके साथ पिछले कई माह से जुड़ा हुआ था।

## ममता को अध्यक्ष पद से हटाया, अभिषेक निलंबित... बागियों ने संभाली TMC की कमान

- पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में बड़ा विद्रोह हुआ है. ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में बागी विधायकों ने ममता बनर्जी को चेयरपर्सन पद से हटाकर अरूप रॉय को नया अध्यक्ष चुना है. अभिषेक बनर्जी को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है
- 60 विधायकों और 70 पार्षदों के समर्थन से बनी इस नई कमेटी ने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है, जिससे पार्टी सिंबल को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पश्चिम बंगाल में ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में बागी तृणमूल कांग्रेस ने अभिषेक बनर्जी को पार्टी से सस्पेंड कर दिया और ममता बनर्जी को पार्टी के चेयरपर्सन पद से हटा दिया. विधायक अरूप रॉय को नया चेयरमैन चुना गया. इस तरह से बागी तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने पार्टी पर कब्जा करने का संकेत दिया. अब नया संगठन बन गया है, क्या बागी इस बार सिंबल के लिए अप्लाई करेंगे? इसे लेकर सवाल किये जा रहे हैं एक नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रम में, ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने सोमवार को ममता बनर्जी द्वारा बनाई गई तृणमूल कांग्रेस पर औपचारिक रूप से कब्जा कर लिया. पार्टी बनने के बाद पहली बार ममता बनर्जी को पार्टी चेयरपर्सन के पद से हटाया दिया गया।

टीएमसी के 60 बागी विधायकों और कम से कम 70 पार्षदों की मौजूदगी में ऋतब्रत गुट ने यह फैसला किया. यह कदम पश्चिम बंगाल के राजनीतिक माहौल में एक बड़ा बदलाव है, जिसमें बागी गुट ने पार्टी के अंदर संगठन और लेजिस्लेटिव सपोर्ट का दावा किया है क्योंकि वह एक नया लीडरशिप स्ट्रक्चर बनाना चाहता है।

### जानें नई कमेटी में किसे मिली जगह

नए तृणमूल जनरल सेक्रेटरीः जावेद खान, संदीपन साहा, रीताब्रत बनर्जी, सबीना यास्मीन.

**कोषाध्यक्षः** अख्तरुज्जमां.

**उपाध्यक्षः** अरूप बिस्वास, फिरहाद हकीम, रथिन घोष.

**चेयरमैनः** अरूप रॉय

### ऋतब्रत ने पार्टी के पार्षदों के साथ की बैठक

इससे पहले आज न्यूटाउन में ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी के बागी पार्षदों की बैठक हुई इस बैठक में करीब 70 पार्षद उपस्थित थे. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के ऐलान के मुताबिक, कोलकाता में कुछ ही महीनों में कोलकाता नगर निगम के चुनाव होंगे. चुनाव दिसंबर तक होने हैं, लेकिन उससे पहले पार्षदों की ये तस्वीरें तृणमूल कांग्रेस में बड़ी फूट की ओर इशारा कर रही हैं। राज्य में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद, शोभनदेव चटर्जी का नाम विपक्ष के नेता के तौर पर विधानसभा भेजा गया. 70 विधायकों के साइन के साथ एक रेजोल्यूशन कॉपी विधानसभा भेजी गई. फिर, एंटाली के विधायक संदीपन साहा और उलुबेरिया पूर्व के विधायक ऋतब्रत बनर्जी ने शिकायत की कि उन्होंने साइन नहीं किए. साइन नकली थे. फिर वे स्पीकर के पास गए और इसकी शिकायत की।

# सुरक्षा की जीत, गरिमा की हार? नीट-यूजी पुनर्परीक्षा का दोहरा चेहरा

**[जब परीक्षा केंद्र बने सुरक्षा किले: क्या यही शिक्षा का भविष्य है?]**

**[बायोमेट्रिक जेल में बंद भविष्य: निष्पक्षता की कीमत या विश्वास का संकट?]**

21 जून 2026 को नीट-यूजी की पुनर्परीक्षा समाप्त हुई। परीक्षा केंद्रों से बाहर निकलते लाखों विद्यार्थियों के चेहरों पर राहत थी, लेकिन आंखों में एक अनकहा बोझ भी झलक रहा था। देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में शामिल इस परीक्षा को अभूतपूर्व सुरक्षा घेरे में आयोजित किया गया। 22 लाख से अधिक अभ्यर्थियों, 95 हजार परीक्षा कक्षों, 1.38 लाख सीसीटीवी कैमरों, 51 हजार जैमरों, हजारों बायोमेट्रिक कर्मचारियों और कड़ी फ्रिस्किंग के बीच परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। पेपर लीक की आशंकाएं लगभग समाप्त रहीं और परिणामों पर विश्वास बहाल होने की उम्मीद जगी। इसके लिए एनटीए और केंद्र सरकार बधाई के पात्र हैं। लेकिन इस सफलता के बीच एक सवाल खड़ा है–क्या निष्पक्षता की यह कीमत हमारी युवा पीढ़ी की गरिमा और मानसिक शांति से वसूली जानी चाहिए?

पिछले वर्षों में बार-बार हुए पेपर लीक कांडों ने परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता को गहरी चोट पहुंचाई थी। मई 2026 की घटना के बाद सरकार और एनटीए ने पूरे तंत्र को लगभग रीसेट कर दिया। प्रश्न-पत्र तैयार करने से लेकर उनके परिवहन तक अभूतपूर्व गोपनीयता बरती गई। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ स्थानों पर भारतीय वायुसेना की सहायता से प्रश्न-पत्र पहुंचाए गए, जीपीएस ट्रैकिंग, पुलिस एस्कॉर्ट और एआई आधारित निगरानी तंत्र सक्रिय किए गए। राष्ट्रीय, राज्य और मंत्रालय स्तर पर रियल-टाइम मॉनिटरिंग हुई। हजारों पर्यवेक्षक, साइबर निगरानी दल और खुफिया एजेंसियों का त्रिस्तरीय सुरक्षा नेटवर्क परीक्षा की हर गतिविधि पर नजर रख रहा। यह व्यवस्था किसी शैक्षणिक आयोजन से अधिक एक राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान जैसी प्रतीत होती थी।

इन उपायों का सकारात्मक परिणाम भी सामने आया। लाखों विद्यार्थियों को भरोसा मिला कि इस बार उनकी मेहनत संगठित नकल या पेपर लीक के कारण व्यर्थ नहीं जाएगी। परीक्षा केंद्रों के बाहर खड़े माता-पिता को भी संतोष था कि उनके बच्चों का भविष्य किसी अपराधी गिरोह या भ्रष्ट नेटवर्क के हाथों बंधक नहीं बनेगा। लंबे समय से अपेक्षित विश्वास बहाली की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम था। निष्पक्षता किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आत्मा है और उसे बचाने के लिए कठोर कदमों का औचित्य स्वीकार किया जा सकता है। किंतु हर सफलता कुछ ऐसे प्रश्न भी छोड़ जाती है जिन्हें केवल आंकड़ों और प्रशंसाओं से ढंका नहीं जा सकता।

सबसे बड़ा प्रश्न उस अनुभव का है जिससे विद्यार्थी गुजरे। आधार आधारित फेस रिकग्निशन, फिंगरप्रिंट सत्यापन, जेबों, कानों, जूतों और यहां तक कि कपड़ों की चेन, जिप तथा धागों तक की जांच–यह सब उस युवा पीढ़ी के साथ हुआ जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर परीक्षा केंद्र पहुंची थी। 38,795 फ्रिस्किंग कर्मी और 48,448 बायोमेट्रिक कर्मचारी व्यवस्था की आवश्यकता को दर्शाते हैं, लेकिन विद्यार्थियों के मन में यह अनुभव भी दर्ज हुआ कि उन पर पहले संदेह किया गया, बाद में विश्वास। कई अभ्यर्थियों ने स्वयं को अपराधियों की तरह टटोला जाता महसूस किया। यह भावना किसी परीक्षा की सफलता का हिस्सा नहीं होनी चाहिए।

इस पूरी प्रक्रिया का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। विशेषकर छात्राओं के लिए फ्रिस्किंग कई बार असहजता और तनाव का कारण बनी। यद्यपि महिला कर्मियों की नियुक्ति की गई थी, फिर भी मानसिक दबाव पूरी तरह समाप्त नहीं हो सका। माता-पिता दूर खड़े अपने बच्चों को डिजिटल और भौतिक निगरानी के घेरे में प्रवेश करते देखते रहे। शिक्षा का मंदिर कई स्थानों पर सुरक्षा चौकी जैसा दिखाई देने लगा। यह दृश्य केवल परीक्षा व्यवस्था का नहीं, बल्कि उस सामाजिक अविश्वास का भी प्रतीक है जो धीरे-धीरे संस्थाओं और नागरिकों के बीच बढ़ता जा रहा है। जब एक छात्र परीक्षा देने से पहले स्वयं को संदिग्ध साबित होने से बचाने की प्रक्रिया से गुजरता है, तब कहीं न कहीं शिक्षा का मूल उद्देश्य भी आहत होता है।

दरअसल समस्या का मूल कारण विद्यार्थी नहीं हैं। समस्या उस व्यवस्था में है जिसने वर्षों तक पेपर लीक, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक कमजोरियों को पनपने दिया। यदि परीक्षा प्रणाली पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीकी रूप से मजबूत होती, तो शायद इतनी कठोर सुरक्षा की आवश्यकता न पड़ती। राधाकृष्णन समिति की सिफारिशें, कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रणाली की ओर संक्रमण, उन्नत डिजिटल सुरक्षा उपाय तथा एनटीए में संरचनात्मक सुधार लंबे समय से चर्चा में रहे हैं।

इस बार की सफलता सिद्ध करती है कि इच्छाशक्ति हो तो व्यवस्था सुधर सकती है। लेकिन यदि सुधार केवल सुरक्षा तक सीमित रहेगा और मूल समस्याएं जस की तस रहेंगी, तो हर वर्ष विद्यार्थियों को इसी प्रकार की कठिन और तनावपूर्ण प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा।

देश को अब तय करना होगा कि भविष्य की परीक्षा प्रणाली कैसी हो। क्या हम हर वर्ष युद्ध जैसी तैयारियां करेंगे, या ऐसे तकनीकी और संस्थागत सुधार विकसित करेंगे जिनसे सुरक्षा और सम्मान दोनों साथ चल सकें? फ्रिस्किंग को अधिक संवेदनशील और कम अपमानजनक बनाया जा सकता है। बायोमेट्रिक सत्यापन में मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। परीक्षा प्रक्रिया को चरणबद्ध, डिजिटल और लीक-प्रूफ बनाया जा सकता है। सुरक्षा का उद्देश्य भय नहीं, विश्वास पैदा करना होना चाहिए। यदि कोई व्यवस्था निष्पक्ष तो हो जाए, पर उसमें मानवीय गरिमा खो जाए, तो वह अधूरी सफलता ही कहलाएगी।

नीट-2026 की पुनर्परीक्षा भारत की परीक्षा प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इस बार परीक्षा सफल रही, विवादों से अपेक्षाकृत मुक्त रही और लाखों छात्रों के परिश्रम को न्याय मिलने की संभावना मजबूत हुई।

यह उपलब्धि छोटी नहीं है। फिर भी यह घटना चेतावनी देती है कि केवल सुरक्षा बढ़ाना समाधान नहीं है। मां-बाप के सपनों से जुड़ी यह व्यवस्था कब तक चलेगी? क्या हम अपने युवाओं को पंख देकर उड़ाना चाहते हैं या उन्हें बायोमेट्रिक सलाखों के बीच भविष्य तलाशने के लिए छोड़ देना चाहते हैं? निष्पक्षता आवश्यक है, पर गरिमा भी उतनी ही आवश्यक है। असली विजय तब होगी जब परीक्षा केंद्र से बाहर निकलता छात्र केवल राहत नहीं, सम्मान और आत्मविश्वास भी महसूस करे।

**प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'**

# योग दिवस: सिर्फ इवेंट बनकर न रह जाए

**संपादक/लेखक: राजीव शुक्ला**

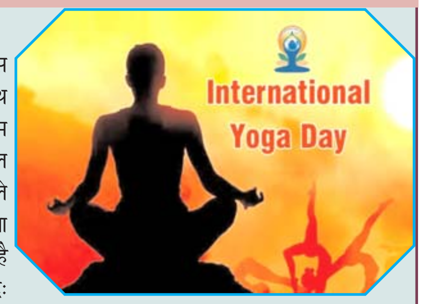


21 जून 2026 को 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस देशभर में मनाया गया। राजधानी दिल्ली के साथ साथ देश के हर शहर और कस्बों में हजारों जगहों पर कार्यक्रम हुए, प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में विशेष सत्र में शामिल हुए। तस्वीरें अच्छी आई, बयानबाजी हुई, और अगले दिन सब सामान्य हो गया। अब सवाल ये है कि क्या योग दिवस सिर्फ एक दिन का इवेंट बनकर रह गया है या इसका जमीनी असर भी दिख रहा है? प्रतीकवाद: जो दिखता है- हर साल 21 जून को योग दिवस का मतलब हो जाता है: सरकारी अधिकारी मैट पर बैठे हुए फोटो, स्कूल-कॉलेज में अनिवार्य ड्रिल, सोशल मीडिया पर सेलेब्स के वीडियो विदेशों में भारतीय दूतावासों के कार्यक्रम, ये सब जरूरी है। इसने योग को ग्लोबल ब्रांड बनाया। 2014 से पहले योग को 'हिंदू प्रैक्टिस' कहकर खारिज किया जाता था। आज 190+ देश इसे मनाते हैं। यूएन ने 2014 में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। लेकिन प्रतीकवाद की सीमा यही है कि वो एक दिन में ही खत्म हो जाता है।

**जमीनी हकीकत:** आंकड़े क्या कहते हैं? सकारात्मक पक्ष- आयुष मंत्रालय के मुताबिक 2024 तक 1.2 लाख से ज्यादा योग इंस्ट्रक्टर ट्रेंड हो चुके हैं। अब योग को भी स्कूलों में शामिल किया जाने लगा है। सीबीएसई ने 6-12 क्लास में योग को पार्ट बनाया है।

**मेडिकल टूरिज्म-,** ऋषिकेश, केरल, मैसूर में योग-आयुर्वेद के लिए विदेशी आ रहे हैं। ये 8000 करोड़ का इंडस्ट्री बन गया है। इसका एक कमजोर पक्ष यह है कि ग्रामीण भारत में इसकी पहुंच बहुत कम या ना के बराबर है। एनसीआरबी का हेल्थ सर्वे कहता है कि 70% ग्रामीण लोग रोज योग नहीं करते। उनके लिए योग 'शहरियों का शौक' है। क्वालिटी का सवाल- 15 दिन के सर्टिफिकेट कोर्स से बने इंस्ट्रक्टर स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। इससे गलत प्रैक्टिस का खतरा है। निरंतरता नहीं- 21 जून के बाद ज्यादातर लोग मैट समेट देते हैं। रोजाना योग करने वालों की संख्या 15% से ज्यादा नहीं बढ़ी। असर कहां दिखना चाहिए था?- योग को स्वास्थ्य नीति का हिस्सा बनना था, लेकिन हुआ नहीं। नॉन-कम्यूनिकेबल डिजीज पर रोक- भारत में डायबिटीज, हाई BP, स्ट्रेस के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। ICMR कहता है कि 2030 तक 13.4 करोड़ लोग डायबिटिक होंगे। योग प्रिवेंटिव हेल्थ में काम करता है, लेकिन आयुष बजट कुल हेल्थ बजट का सिर्फ 2.3% है। मानसिक स्वास्थ्य- NIMHANS के डेटा के मुताबिक भारत में 15% लोग मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। योग और प्राणायाम का असर डिप्रेशन-एंग्जाइटी में साबित है। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में योग को मेनस्ट्रीम नहीं किया गया। स्कूलों में योग पीरियड है, लेकिन परीक्षा में नहीं पूछा जाता। बच्चे 45 मिनट करके भूल जाते हैं। अगर इसे फिजिकल एजुकेशन का ग्रेड हिस्सा बनाया जाए तो आदत बने। दूसरे देशों ने क्या किया?- अमेरिका में 20,000 से ज्यादा स्कूलों में 'Yoga in Schools' प्रोग्राम चलता है। इंश्योरेंस कंपनियां योग करने वालों को प्रीमियम में छूट देती हैं। चीन में ताई-ची को नेशनल फिटनेस प्रोग्राम बनाया। हर पार्क में सुबह ग्रुप प्रैक्टिस होती है। भारत में हम इवेंट कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक हेल्थ सिस्टम में योग को इंटीग्रेट नहीं किया। सवाल यह उठता है कि अब क्या करना चाहिए? प्रतीकवाद से हटकर पॉलिसी बनाओ। योग दिवस को सिर्फ इवेंट न रखो। हर जिला अस्पताल में योग थेरेपी सेंटर हो। आयुष्मान भारत में योग कवर हो। क्वालिटी कंट्रोल ऐसा हो जो भी योग सिखाए, उसकी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन सख्त हो। गलत आसन से स्पाइन इंजरी के केस बढ़ रहे हैं। ग्रामीण फोकस- हर पंचायत में एक योग मित्र हो। जैसे आशा वर्कर है, वैसे ही योग वर्कर। उन्हें स्टाइपेंड मिले। डेटा पर काम करो- योग से कितने लोगों का शुगर कंट्रोल हुआ, कितनों की दवा कम हुई- ये डेटा इकट्ठा करो। तभी पॉलिसी मेकर मानेंगे। योग दिवस का महत्व कम नहीं हुआ है। इसने भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ाई है। लेकिन अगर अगले 10 साल भी हम सिर्फ 21 जून को मैट बिछाते रहे, तो योग 'इंस्टाग्रामेबल एक्टिविटी' बनकर रह जाएगा। योग का असली मकसद था- 'योगः कर्मसु कौशलम्'। काम में कुशलता। वो कुशलता तब आएगी जब योग स्कूल की क्लास से निकलकर अस्पताल की OPD, फैक्ट्री के ब्रेक रूम और गांव के चौपाल तक पहुंचे। तस्वीरें अच्छी लगती हैं, लेकिन बदलाव तब दिखता है जब किसी गांव के डायबिटिक मरीज की दवा आधी हो जाए क्योंकि उसने रोज 30 मिनट अनुलोम-विलोम किया।

# आस्था की कीमत जीवन से चुका रहे हैं श्रद्धालु?

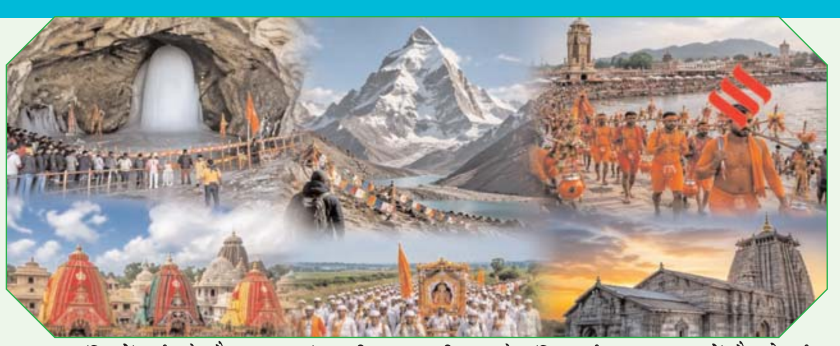

आए दिन तीर्थ स्थलों मंदिरों स्नान और दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को आस्था की कीमत जान देकर चुकानी पड़ रही है। हमारे मंदिरों तीर्थस्थलों पर व्यवस्थाएं इतना निम्न स्तर पर पहुंच चुकी हैं कि न भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशासन सटीक निर्णय ले पाता है न मंदिरों की व्यवस्था की जिम्मेदार प्रबंधन कमेटी श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जागरूक हैं यही वजह है कि पुरी जगन्नाथ यात्रा से लेकर वैष्णो देवी धाम तक कुंभ स्नान से लेकर मनसा देवी पावागढ मंदिर तक हादसों में अनेक बेगुनाह श्रद्धालुओं को जीवन गंवाना पड़ता है। ताज़ा हादसा महाराष्ट्र के परभणी जिले की मानवत तहसील स्थित यशवाड़ी मारुति मंदिर में बीते शनिवार को हुआ दर्दनाक हादसा पूरे देश को झकझोर देने वाला है। मंदिर परिसर के सामने बना सभा मंडप अचानक भरभराकर गिर पड़ा, जिसके कारण कई श्रद्धालु मलबे में दब गए। प्रारंभिक रिपोटों में मृतकों की संख्या पांच बताई गई, जबकि बाद में विभिन्न स्थानीय स्रोतों और प्रशासनिक सूचनाओं में छह लोगों की मृत्यु तथा अनेक श्रद्धालुओं के घायल होने की जानकारी सामने आई। लगभग 30 से 40 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई गई थी और बचाव दलों ने घंटों तक राहत एवं बचाव अभियान चलाकर लोगों को बाहर निकाला। कई घायलों का उपचार विभिन्न अस्पतालों में जारी है। इस हादसे ने केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश के सामने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमारी धार्मिक आस्था के केंद्र पर्याप्त रूप से सुरक्षित हैं।

मंदिरों में होने वाली दुर्घटनाएं मुख्य रूप से भीड़ अनियंत्रित होने (भगदड़), कमजोर निर्माण (छत या पिलर गिरना), बिजली के करंट, या आग लगने के कारण होती हैं। महाराष्ट्र के परभणी के यशवाड़ी हनुमान मंदिर में दर्शन के दौरान सभा मंडप की छत अचानक भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में 5 से 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

पिछले दिनों यूपी के वृन्दावन में इस्कॉन मंदिर के गेट पर नगर निगम द्वारा लगाए गए शॉवर कूलर में अचानक करंट उतर आया। इसकी चपेट में आने से एक 21 वर्षीय श्रद्धालु की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पिछले दिनों महाराष्ट्र के सिद्धिनाथ मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी अनियंत्रित होकर एक गहरे कुएं में जा गिरी, जिससे 9 लोगों की जान चली गयी। राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में उमड़ने वाली भारी भीड़, कुप्रबंधन, और उचित कतारें न होने के कारण अक्सर भगदड़ और विवाद जैसी स्थितियां सामने आती है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में स्थित विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के समीप एक हृदयविदारक हादसा सामने आया है। मंदिर के गेट नंबर 5 के पास स्थित एक गली में अचानक एक पुराने मकान का छज्जा गिर गया, जिसकी चपेट में आने से वहां से गुजर रहे कई श्रद्धालु घायल हो गए। बीते साल मौसम विभाग की चेतावनी को दरकिनार कर माता वैष्णो देवी की यात्रा जारी रखी गई जिस के चलते 34 श्रद्धालुओं की माता के मंदिर मार्ग पर भूस्खलन में मौत हो गई। इसके अलावा अगस्त 2025 में ही मनसा देवी पर भी आधा दर्जन तीर्थयात्रियों की भगदड़ में मौत हो गई थी। हादसों का सिलसिला लम्बा है और लगातार जारी है।

आपको बता दें कि भारत आस्था और श्रद्धा का देश है। यहां प्रतिदिन लाखों लोग मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और अन्य धार्मिक स्थलों पर पहुंचते हैं। विशेष अवसरों पर श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में इन स्थानों की संरचनात्मक मजबूती और सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। परभणी की घटना केवल एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि यह उन व्यवस्थागत कमियों की ओर संकेत करती है जिन्हें लंबे समय से नजरअंदाज किया जाता रहा है। यदि किसी निमार्णाधीन अथवा मरम्मताधीन ढांचे में श्रद्धालुओं की आवाजाही जारी रहती है तो यह सीधे सीधे मानव जीवन को जोखिम में डालने जैसा है।

सबसे गंभीर प्रश्न यह है कि जिस सभा मंडप में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, उसकी तकनीकी जांच कब और किस स्तर पर हुई थी। यदि निर्माण कार्य चल रहा था तो क्या सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था? क्या संबंधित विभागों ने समय-समय पर निरीक्षण किया था? क्या मंदिर प्रबंधन समिति ने संभावित खतरे को देखते हुए श्रद्धालुओं के प्रवेश को नियंत्रित करने का प्रयास किया था? इन प्रश्नों के उत्तर केवल प्रशासनिक औपचारिकता नहीं हैं, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की दिशा तय करेंगे।

दुर्भाग्य से यह कोई पहला मामला नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक स्थलों पर भगदड़, दीवार गिरने, छत ढहने और अन्य दुर्घटनाओं में अनेक लोगों की जान जा चुकी है। हाल ही में महाराष्ट्र के सांगली जिले में भी मंदिर परिसर से जुड़ी एक दुर्घटना में कई श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई थी। ऐसी घटनाएं बताती हैं कि समस्या किसी एक स्थान या एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यापक स्तर पर सुरक्षा प्रबंधन की चुनौती है।

वास्तविकता यह है कि अनेक धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन आधारभूत ढांचे का विस्तार और रखरखाव उसी गति से नहीं हो पा रहा। कई स्थानों पर अस्थायी शेड, मंडप और अन्य संरचनाएं बिना पर्याप्त तकनीकी परीक्षण के उपयोग में लाई जाती हैं। कई बार निर्माण कार्य स्थानीय स्तर पर करवा लिया जाता है, लेकिन इंजीनियरिंग मानकों और गुणवत्ता नियंत्रण की अनदेखी हो जाती है। जब तक कोई दुर्घटना नहीं होती, तब तक इन कमियों पर गंभीर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रत्येक घटना के बाद केवल शोक व्यक्त करना पर्याप्त नहीं होगा। आवश्यक है कि राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन इस हादसे की निष्पक्ष जांच कराएं। यदि निर्माण में लापरवाही, गुणवत्ता में कमी या सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।

**मनोज कुमार अग्रवाल**

# 500 करोड़ की तरफ बढ़ा पेद्दी, राम चरण की स्पोर्ट्स ड्रामा ने दुनियाभर में कमाई से किया राज

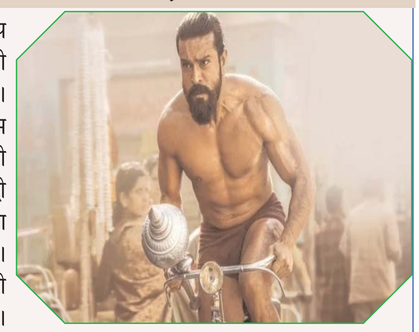

**नई दिल्ली।** साउथ फिल्म इंडस्ट्री के लोकप्रिय अभिनेता राम चरण का नाम फिल्म पेद्दी की कमर्शियल सफलता को लेकर चर्चा में बना हुआ है। घरेलू बॉक्स ऑफिस के अलावा विदेशों में भी राम की पेद्दी कमाई के मामले में धमाकेदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि अब पेद्दी वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में 500 करोड़ का जादुई आंकड़े छूने की तैयारी में निकल पड़ी है। आइए जानते हैं कि अब तक ये स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी इंटनेशनल मार्केट में कितना बिजनेस कर चुकी है।

**वर्ल्डवाइड पेद्दी ने किया कमाल**

राम चरण और जाह्नवी कपूर स्टारर पेद्दी को बीते 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। तब से लेकर अब तक ये फिल्म बंपर कमाई की लय को बरकरार रखी हुई है और हर रोज मोटा पैसा छाप रही है। सिर्फ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, बल्कि विदेशी बाजार में भी इस फिल्म कामयाबी का परचम लहराया है।

अब तक पेद्दी की रिलीज को 18 दिनों का समय बीता है और गौर किया जाए इसके वर्ल्डवाइड कलेक्शन के टोटल आंकड़े की तरफ तो एशियन बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट के अनुसार वह 443 करोड़ हो गया है, जोकि एक प्रभावशाली कमाई का आंकड़ा माना जा रहा है।

जल्द ही पेद्दी 450 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी और इसकी पूरी कोशिश रहेगी कि मूवी का लाइफटाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन कैसे भी 500 करोड़ के क्लब में एंट्री ले ले। हालांकि, ये इतना आसान होने वाला नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आर आर आर के बाद पेद्दी दूसरी ऐसी फिल्म होगी, जो ग्लोबली 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई करेगी। मालूम हो कि निर्देशक एस एस राजामौली के डायरेक्शन में बनने वाली आर आर आर ने दुनियाभर में 1200 करोड़ से ज्यादा बिजनेस किया था।

**इन मूवीज पर भारी पड़ी पेद्दी**

मौजूदा समय में शाहिद कपूर स्टारर कॉकेटल 2 और समांथा रुथ प्रभु की 'मां इंति बंगारम' जैसी कई लेटेस्ट फिल्में कमाई के मामले में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। इसके बावजूद पेड्डी ने अपना दबदबा बनाए रखा है। इससे पहले राम चरण की पेद्दी ने कमाई के मामले में है जवानी तो इश्क होना है, बंदर, भारत भाग्य विधाता और मैं वापस आऊंगा जैसी मूवीज को पछाड़ा है।

# दैनिक राशिफल

**मेष** आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार के साथ समय सुखद रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

**वृषभ** धैर्य और समझदारी से काम लें। धन संबंधी मामलों में लाभ के योग हैं। नौकरी में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। अनावश्यक विवादों से बचें।

**मिथुन** नए संपर्क लाभदायक सिद्ध होंगे। व्यापार में उन्नति के संकेत हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। यात्रा के योग बन सकते हैं।

**कर्क** भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लें। कार्यक्षेत्र में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

**सिंह** भाग्य का साथ मिलेगा। रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। नौकरी और व्यापार में सफलता के अवसर मिलेंगे। सम्मान में वृद्धि होगी।

**कन्या** आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। खर्चों पर नियंत्रण आवश्यक है। करियर में नई संभावनाएं सामने आ सकती हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

**तुला** साझेदारी के कार्यों में लाभ होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा।

**वृश्चिक** कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। मेहनत और लगन से सफलता मिलेगी। शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा। धन लाभ के योग हैं।

**धनु** रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। शिक्षा और करियर के क्षेत्र में शुभ समाचार मिल सकता है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

**मकर** घर-परिवार से जुड़े मामलों में व्यस्तता रहेगी। संपत्ति संबंधी कार्यों में लाभ हो सकता है। नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी।

**कुंभ** संचार और संपर्क से लाभ मिलेगा। छोटे भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। यात्रा शुभ रहेगी।

**मीन** आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

**करियर राशिफल (22 जून 2026)**

**मेष, सिंह, धनु:** पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के योग।

**वृषभ, कन्या, मकर:** मेहनत का फल मिलेगा, आर्थिक लाभ संभव।

**मिथुन, तुला, कुंभ:** नए संपर्क और नेटवर्किंग से करियर में फायदा।

**कर्क, वृश्चिक, मीन:** धैर्य और एकाग्रता से कार्य करने पर सफलता मिलेगी।

# बंदूक के साये से परिवार की छांव तक नक्सल हिंसा की त्रासदी, मानवीय पुनर्वास और सभ्य समाज की जिम्मेदारी

छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र से सामने आई एक खबर केवल प्रशासनिक पहल या चिकित्सा उपलब्धि भर नहीं है, बल्कि यह उस लंबे दर्दनाक अध्याय की याद दिलाती है जिसने हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। जिन लोगों ने वर्षो तक बंदूक, भय, हिंसा और अनिश्चितता के बीच जीवन बिताया, वे आज सामान्य पारिवारिक जीवन की ओर लौटने का प्रयास कर रहे हैं। आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों के लिए रिवर्स वासेक्टॉमी जैसी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना और उन्हें विवाह तथा पारिवारिक जीवन की मुख्यधारा से जोड़ना केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि मानव गरिमा की पुनर्स्थापना का प्रयास है।

नक्सलवाद का इतिहास केवल सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच संघर्ष की कहानी नहीं है। इसके पीछे असंख्य ऐसे मानवीय दुख छिपे हैं जिनकी चर्चा अक्सर नहीं होती। जंगलों में सक्रिय संगठनों के कठोर अनुशासन के कारण व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगाए जाते रहे हैं। अनेक रिपोर्टों और अनुभवों में सामने आया है कि संगठन के भीतर प्रेम, विवाह और परिवार जैसी स्वाभाविक मानवीय भावनाओं को कमजोरी माना जाता था। कई लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध जीवन जीना पड़ा। ऐसे माहौल में व्यक्ति की पहचान एक इंसान के रूप में नहीं, बल्कि केवल एक लड़ाके के रूप में सीमित होकर रह जाती है।

जब किसी व्यक्ति से उसका पारिवारिक जीवन छीन लिया जाता है, तब केवल उसकी स्वतंत्रता ही नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी प्रभावित होता है। परिवार मनुष्य के जीवन की सबसे मूलभूत सामाजिक इकाई है। माता-पिता बनने का सपना, जीवनसाथी के साथ सुख-दुख साझा करने की इच्छा और बच्चों के भविष्य को संवारने की आकांक्षा हर व्यक्ति के भीतर स्वाभाविक रूप से मौजूद रहती है। यदि किसी व्यवस्था या विचारधारा के कारण इन अधिकारों का दमन होता है, तो यह केवल व्यक्तिगत पीड़ा नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा पर भी आघात है।

बस्तर में आत्मसमर्पण कर चुके पूर्व नक्सलियों के जीवन में आए बदलाव इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। जो लोग कभी बंदूक उठाने को मजबूर थे, वे अब सम्मानजनक जीवन, रोजगार, परिवार और सामाजिक स्वीकृति की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। यह परिवर्तन दर्शाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, मनुष्य के भीतर सामान्य जीवन की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। हिंसा का रास्ता अंततः व्यक्ति को अकेलापन, भय और असुरक्षा ही देता है, जबकि समाज की मुख्यधारा उसे अपनापन और स्थिरता प्रदान करती है।

रिवर्स वासेक्टॉमी अभियान का मानवीय पक्ष विशेष रूप से उल्लेखनीय है। चिकित्सा विज्ञान का उपयोग यहां केवल एक शारीरिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन लोगों को जीवन की नई उम्मीद देने का माध्यम बन रहा है जिनसे कभी पितृत्व का अधिकार छीन लिया गया था। जब कोई पूर्व नक्सली अपनी गोद में अपने बच्चे को उठाता है, तो वह केवल एक पिता नहीं बनता, बल्कि हिंसा से शांति की ओर यात्रा का प्रतीक भी बन जाता है। यह दृश्य बताता है कि समाज में पुनर्वास और पुनर्समावेशन की प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है। हालांकि इस पूरे प्रसंग का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ऐसी परिस्थितियां पैदा क्यों हुईं, जिनमें लोगों को अपनी प्राकृतिक इच्छाओं और अधिकारों से वंचित होना पड़ा। दशकों तक चले नक्सली संघर्ष ने केवल विकास को बाधित नहीं किया, बल्कि सामाजिक संरचना को भी गहरे घाव दिए हैं। अनेक परिवार टूटे, बच्चों ने माता-पिता को खोया, गांवों में भय का वातावरण बना रहा और विकास की प्रक्रिया प्रभावित हुई। हिंसा का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि वह समाज के सामान्य जीवन को असामान्य बना देती है।

आज जब कुछ पूर्व नक्सली विवाह कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं और समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं, तब यह केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं है। यह उन सभी प्रयासों की सफलता है जो शांति, पुनर्वास और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देते हैं। किसी भी संघर्षग्रस्त क्षेत्र में स्थायी समाधान केवल सुरक्षा अभियानों से नहीं आता। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक स्वीकृति और मानवीय संवेदनाओं का भी उतना ही महत्व होता है। जब समाज किसी भटके हुए व्यक्ति को दूसरा अवसर देता है, तभी वास्तविक परिवर्तन संभव होता है।

इस संदर्भ में सभ्य समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। आत्मसमर्पण करने वाले लोगों को संदेह की दृष्टि से देखने के बजाय उन्हें नए जीवन की शुरुआत करने का अवसर दिया जाना चाहिए। यदि वे वास्तव में हिंसा छोड़कर शांति का मार्ग अपनाना चाहते हैं, तो समाज का दायित्व है कि वह उन्हें स्वीकार करे। पुनर्वास केवल सरकारी योजनाओं से पूरा नहीं होता, बल्कि सामाजिक स्वीकार्यता से ही सफल बनता है। रोजगार, शिक्षा और सम्मानजनक व्यवहार उनके आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं और उन्हें दोबारा हिंसा के रास्ते पर लौटने से रोकते हैं।

यह भी सच है कि जिन लोगों ने वर्षों तक बंदूक के साये में जीवन बिताया है, उनके मन पर गहरे मानसिक और भावनात्मक घाव होते हैं। उन्हें केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक सहयोग और सामाजिक समर्थन की भी आवश्यकता होती है। उनके अनुभव दर्द, भय और असुरक्षा से भरे होते हैं। ऐसे लोगों को सामान्य जीवन में लौटाने के लिए संवेदनशील और दीर्घकालिक प्रयास जरूरी हैं। समाज यदि उनके घावों को समझे और उन्हें नई पहचान बनाने का अवसर दे, तो पुनर्वास की प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो सकती है।

बस्तर की यह कहानी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निराशा के बीच आशा का संदेश देती है। यह बताती है कि हिंसा और संघर्ष की सबसे अंधेरी परिस्थितियों से भी जीवन की नई शुरुआत संभव है। जिन हाथों में कभी बंदूक थी, वे आज अपने बच्चों को दुलार रहे हैं। जिन लोगों के सामने कभी केवल संघर्ष और मृत्यु का रास्ता था, वे अब परिवार और भविष्य के सपने देख रहे हैं। यह परिवर्तन किसी भी सभ्य समाज के लिए सकारात्मक संकेत है।

**अंततः** यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि हर व्यक्ति के भीतर एक सामान्य और सम्मानजनक जीवन जीने की आकांक्षा होती है। हिंसा उस आकांक्षा को दबा सकती है, लेकिन समाप्त नहीं कर सकती। इसलिए आवश्यक है कि समाज ऐसे दर्दभरे अध्यायों से सीख ले और उन लोगों को नई शुरुआत का अवसर दे जो संघर्ष की दुनिया से निकलकर शांति के मार्ग पर चलना चाहते हैं। बंदूक के साये में घटित मानवीय त्रासदियों से उबरने का सबसे प्रभावी तरीका यही है कि हम संवेदना, पुनर्वास और सामाजिक समावेशन को प्राथमिकता दें। तभी उन घरों में स्थायी खुशियां लौट सकेंगी, जहां कभी भय और असुरक्षा का अंधेरा पसरा हुआ था।

**कांतिलाल मांडोत**

**स्वामी-** स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ल द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला बिजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचाद तहसील व जनपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तमे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोट:** उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.NI NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com

## संक्षिप्त खबरें

### सड़क हादसे में 19 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल जिला अस्पताल रेफर

**महराजगंज/रायबरेली।** कोतवाली क्षेत्र में सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 19 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस समय हुआ जब युवक अपने बड़े भाई को छोड़कर वापस घर लौट रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार, आदर्श सोनी (19 वर्ष) पुत्र सत्येंद्र सोनी निवासी ग्राम हिलहा अपने बड़े भाई को हलोर छोड़ने गए थे। वापस लौटते समय सुबह करीब 11 बजे जमुरावा गांव स्थित शिव मंदिर के पास सामने से आ रही एक अज्ञात तेज रफ्तार बाइक ने उनकी मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि आदर्श गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े और उनकी मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद अज्ञात बाइक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना ग्रामीणों ने परिजनों को दी। परिजन तत्काल घायल युवक को निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) महराजगंज लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रायबरेली रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में जांच के उपरांत हालत नाजुक पाए जाने पर चिकित्सकों ने उसे एम्स रायबरेली भेज दिया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद परिजनों में चिंता का माहौल है।

### जमीन विवाद में महिलाओं पर हमला, पांच घायल; मुकदमा दर्ज

**गोपीगंज।** बिन्दु देवी पत्नी राकेश कुमार शुक्ला ग्राम दुहिया चकसुंदरपुर थाना ज्ञानपुर ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र के जमीनी विवाद में पीड़िता के अनुसार, मंदिर में पूजा के दौरान विवाद के बाद विपक्षी महिलाओं ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। बीच-बचाव करने पहुंचे परिवार के चार अन्य सदस्य भी मारपीट में घायल हो गए। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि रीता देवी, संगीता (तनुजा) एवं उर्मिला देवी द्वारा आए दिन जमीन विवाद को लेकर गाली-गलौज और मारपीट की जाती है तथा झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जाती है। घटना में कुल पांच लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

### डीएम की सख्ती, तालाब की भूमि से हटेगा अतिक्रमण

**वारी में लापरवाही पर लेखपाल के निलंबन के निर्देश**

**भदोही।** सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को उन्होंने नगर पंचायत ज्ञानपुर और ग्राम पंचायत उवारी का स्थलीय निरीक्षण कर अवैध कब्जों के मामलों में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। ज्ञानपुर में पुराने दीवानी परिसर के निकट स्थित तालाब की भूमि पर मिट्टी डालकर कब्जा किए जाने की शिकायत पर जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच में शिकायत प्रथम दृष्टया सही मिलने पर उन्होंने तहसीलदार को संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा जेसीबी से मिट्टी हटाकर तालाब को मूल स्वरूप में बहाल कराने के निर्देश दिए। इसके बाद जिलाधिकारी ग्राम पंचायत वारी पहुंचे, जहां ग्राम समाज की नवीन परती भूमि पर कब्जे के प्रयास की शिकायत मिली थी। निरीक्षण के दौरान भूमि संरक्षण में लापरवाही पाए जाने पर उन्होंने संबंधित लेखपाल राकेश कुमार को निलंबित किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही तहसीलदार को भूमि का सीमांकन कराकर कब्जामुक्त कराने तथा दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। जिलाधिकारी ने कहा कि तालाब, चारागाह, परती तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी एसडीएम को नियमित निरीक्षण कर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्तियां जनता की धरोहर हैं और उनकी सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकारी भूमि की सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

# राम मंदिर चढ़ावा विवाद: हाई कोर्ट ने जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार

**● इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे के कथित दुरुपयोग की जांच वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।**

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**लखनऊ।** इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सोमवार को अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर में प्राप्त चढ़ावे के कथित दुरुपयोग एवं वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर तत्काल एवं क्रम से हटकर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अवकाशकालीन पीठ के न्यायमूर्ति पंकज भाटिया और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय ने मौखिक रूप से कहा कि मामले में ऐसी कोई तात्कालिकता नहीं है, जिसके आधार पर इसे अन्य मामलों से पहले सुना जाए। यह टिप्पणी उस समय की गई जब याचिकाकर्ता मोहित अशोक ने अदालत के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए इसकी तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। इस पर पीठ ने कहा कि उसके समक्ष पहले से ही बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं और ऐसे में इस याचिका को क्रम से हटकर सुनने का कोई औचित्य नहीं बनता। पीठ ने यह भी मौखिक रूप से कहा कि राज्य सरकार पहले ही इस मामले में संज्ञान ले चुकी है और आवश्यक पहल कर रही है। ऐसे में तत्काल सुनवाई की कोई विशेष आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। उल्लेखनीय है कि सोमवार को खंडपीठ के समक्ष 529 नए मामले सूचीबद्ध थे। वहीं, मोहित अशोक की जनहित याचिका वाद सूची में क्रम संख्या 392 पर पहले से सूचीबद्ध है। याचिका में राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चढ़ावे की राशि के कथित गबन और वित्तीय अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही पूरे मामले का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) से ऑडिट कराने का भी अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि मंदिर में प्राप्त दान और चढ़ावे के प्रबंधन में वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। याचिका में मंदिर निधि के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की गई है। हालांकि, खंडपीठ ने तत्काल सुनवाई की मांग खारिज करते हुए मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की। अब याचिका पर उसकी निर्धारित क्रम संख्या के अनुसार सुनवाई होने की संभावना है।

## ऑपरेशन दहन के तहत 1.63 करोड़ के मादक पदार्थ नष्ट

**भदोही।** पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे 'ऑपरेशन दहन' अभियान के तहत भदोही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न थानों में बरामद अवैध मादक पदार्थों का नियमानुसार विनिष्टीकरण कराया। जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी (डीडीसी) की देखरेख में कुल 316.465 किलोग्राम मादक पदार्थ नष्ट किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 63 लाख 40 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा यह कार्रवाई की गई। नष्ट किए गए मादक पदार्थों में 316.400 किलोग्राम गांजा तथा 65 ग्राम डायजापाम शामिल है। यह माल जनपद के पांच थानों सुरियावां, ऊंज, भदोही, ज्ञानपुर और दुर्गागंज में दर्ज कुल 10 अभियोगों से संबंधित था। न्यायालय के आदेश एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप सोमवार को प्रयागराज जनपद के थाना हंडिया क्षेत्र स्थित धानूपुर में 'संगम मेडिसर्व प्राइवेट लिमिटेड' के इन्सिनेटर के माध्यम से मादक पदार्थों का विनिष्टीकरण कराया गया। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने बताया कि मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी है। अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा समाज को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।

## पीएम नरेन्द्र मोदी ने मृतकों के परिवारजनों को दो-दो और मुख्यमंत्री ने दी पांच-पांच लाख रुपये की सहायता

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**लखनऊ।** राजधानी लखनऊ में सोमवार दोपहर अलीगंज के पुरनिया/सेक्टर डी क्षेत्र में एक तीन मंजिला भवन में भयानक आग की चपेट में आकर 18 लोगों ने दम तोड़ दिया और 12-13 गंभीर रुप से घायल हैं। तीन मंजिला इमारत में लगी आग ने नीचे की दुकान से शुरू होकर ऊपर चल रही कोचिंग और गेमिंग स्टूडियो को अपनी चपेट में ले लिया। इस अग्निकांड से पीएम नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद आहत हैं। पीएम नरेन्द्र मोदी ने मृतक के परिवारीजन को दो-दो लाख और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा की है। पीएम नरेन्द्र मोदी ने लखनऊ के भीषण अग्निकांड पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों के परिवारजनों को केंद्र की ओर से दो-दो लाख रुपए मुआवजा दिए जाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही घायलों को 20-20 हजार रुपये और उचित इलाज प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निकांड में मृतकों के परिवार का लोगों को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। उन्होंने घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। इसके साथ ही सभी को समुचित इलाज भी मुहैया कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने केजीएमयू के ट्रामा सेंटर में भर्ती घायलों का हालचाल लिया और सभी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने अग्नि दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया एवं किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय पहुंचकर दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में घायल हुए लोगों एवं उनके परिवार के लोगों से भेंट कर उनका कुशल-क्षेम जाना व चिकित्सकों से घायलों के उपचार के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि सभी घायलों का समुचित उपचार कुशल चिकित्सकों के नेतृत्व में शीर्ष प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इस हृदय विदारक दुर्घटना में अपनों को खोने वाले परिवारों का दुःख शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता। प्रदेश सरकार सभी पीड़ित परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।

## 12 वर्षों से अंतर्जनपदीय स्थानांतरण से वंचित वरिष्ठ शिक्षकों का शिक्षा निदेशालय पर धरना

**● सभी शिक्षकों से आवेदन लेकर ट्रांसफर करने की मांग**

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**लखनऊ।** राजधानी लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग में चल रही अंतर्जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया के बीच 12 वर्षों से अधिक समय से स्थानांतरण से वंचित वरिष्ठ शिक्षकों ने सोमवार को शिक्षा निदेशालय पर धरना देकर अपनी नाराजगी जताई। शिक्षकों का आरोप है कि विभाग की वर्तमान व्यवस्था और भारांक नीति के कारण वर्षों से सेवा दे रहे सामान्य श्रेणी के अध्यापकों की लगातार अनदेखी की जा रही है। धरने में शामिल शिक्षक राजीव गौड़ ने कहा कि वर्तमान में अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया संचालित हो रही है, लेकिन सामान्य अध्यापकों से आवेदन पत्र ही नहीं लिए जा रहे हैं। विभाग की ओर से जनगणना कार्य का हवाला देते हुए स्थानांतरण प्रक्रिया रोकने की बात कही जा रही है, जबकि पिछले कई वर्षों से बिना भारांक वाले वरिष्ठ शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गलत भारांक नीतियों के कारण जूनियर शिक्षकों के स्थानांतरण हो जाते हैं, लेकिन वरिष्ठ शिक्षक बार-बार उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। प्रांतीय स्थानांतरण समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष तीर्थमणि त्रिपाठी ने कहा कि उनकी मांग है कि सभी अध्यापकों से अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के आवेदन लिए जाएं और स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाए। यदि जनगणना कार्य के कारण तत्काल कार्यमुक्त करना संभव नहीं है, तो शिक्षकों को जनगणना कार्य समाप्त होने के बाद कार्यमुक्त किया जा सकता है, लेकिन आवेदन लेने की प्रक्रिया नहीं रोकी जानी चाहिए। धरने पर बैठे शिक्षकों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरने में विजय पांडेय, राहुल पुरोहित, शिव प्रताप तिवारी, सविता गुप्ता, नम्रता गुप्ता, कल्पना निगम सहित बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे।

### बहन से छेड़छाड़ और जबरन शादी का दबाव, युवक ने मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार

**उन्नाव।** शहर के आदर्श नगर, नहर किनारा बगिया रोड स्थित मकान संख्या 786 के निवासी रोमी सोनकर पुत्र रमेश सोनकर ने एक युवक पर अपनी बहन के साथ छेड़छाड़ करने, जबरन शादी का दबाव बनाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मामले की शिकायत उन्होंने 20 जून 2026 को जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज कराई है। रोमी सोनकर का आरोप है कि विजय सोनकर पिछले लगभग तीन महीनों से उनकी बहन शिखा सोनकर (बदला हुआ नाम) के साथ लगातार छेड़छाड़ कर रहा है और उस पर जबरन शादी करने का दबाव बना रहा है। आरोप है कि विरोध करने पर वह जान से मारने की धमकी देता है तथा सोशल मीडिया के माध्यम से बदनाम करने की बात कहकर परिवार को भयभीत कर रहा है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि इस संबंध में जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की गई है। रोमी सोनकर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले में निष्पक्ष जांच कराते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने और दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की है, ताकि इस प्रकार की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

## स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, लखनऊ में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2026 का उत्साहपूर्वक आयोजन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**लखनऊ।** राजधानी लखनऊ में 21 जून 2026 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस (एस.एम.एस.), लखनऊ के वैदिक विज्ञान केंद्र के तत्वावधान में संस्थान के गोदावरी प्रांगण में एक भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में सहभागिता कर योग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। योग शिविर का संचालन वैदिक विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष डॉ. भरत राज सिंह द्वारा किया गया। उन्होंने उपस्थित प्रतिभागियों को विभिन्न योगासनों, प्राणायाम तथा ध्यान की विधियों का अभ्यास कराया तथा उनके वैज्ञानिक एवं स्वास्थ्यवर्धक लाभों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। अपने संबोधन में डॉ. सिंह ने कहा कि नियमित योगाभ्यास न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाता है, बल्कि मानसिक संतुलन, एकाग्रता, सकारात्मक सोच एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान तनावपूर्ण जीवनशैली में योग स्वस्थ एवं संतुलित जीवन का सबसे प्रभावी माध्यम है तथा प्रत्येक व्यक्ति को इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। शिविर में उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने पूर्ण उत्साह, अनुशासन एवं समर्पण भाव के साथ योगाभ्यास किया। इस अवसर पर डीन छात्र कल्याण डॉ. पी.के. सिंह, डीन अभियंत्रण डॉ. ज्ञानेंद्र गुप्ता, प्राचार्य (डिप्लोमा) डॉ. अमरजीत सिंह, विभागाध्यक्ष डॉ. आशा कुलश्रेष्ठ, इन्क्यूबेशन मैनेजर डॉ. अरुणेश श्रीवास्तव, प्रशासन प्रबंधक उग्रसेन सिंह, अंकित सिंह, हॉस्टल वार्डन सहित संस्थान के अन्य अधिकारी, कर्मचारी एवं 50 से अधिक विद्यार्थियों ने सक्रिय सहभागिता की। कार्यक्रम का समापन स्वस्थ, जागरूक, तनावमुक्त एवं योगमय समाज के निर्माण के सामूहिक संकल्प के साथ हुआ। प्रतिभागियों ने योग को जीवनशैली का हिस्सा बनाकर राष्ट्र को स्वस्थ एवं सशक्त बनाने का संकल्प लिया।

## सरकारी और किसानों की जमीनों पर अवैध कब्जों के विरोध में 29 जून को लखनऊ में होगा मंडल आयुक्त कार्यालय का घेराव

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**लखनऊ।** नव भारतीय किसान संगठन परिवार ने प्रदेशभर के किसानों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से 29 जून 2026 को लखनऊ में आयोजित होने वाले विशाल किसान प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। संगठन का कहना है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में सरकारी भूमि और किसानों की जमीनों पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जे एवं फर्जी तरीके से भूमि बिक्री के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन संबंधित राजस्व विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला द्वारा जारी सूचना के अनुसार, हरिद्वार में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन एवं चिंतन शिविर में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई थी। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि किसानों की भूमि की सुरक्षा और सरकारी जमीनों को भूमाफियाओं से मुक्त कराने के लिए प्रदेशव्यापी जनआंदोलन चलाया जाएगा। इसी क्रम में 29 जून को लखनऊ में मंडल आयुक्त कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया गया है। संगठन ने प्रदेश के सभी प्रदेश पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों, जिला अध्यक्षों तथा किसान साथियों से बड़ी संख्या में लखनऊ पहुंचकर आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है। संगठन का आरोप है कि बाहरी लोगों को भूखंड बेचने के नाम पर कुछ भूमाफिया सरकारी जमीनों को निजी संपत्ति बताकर अवैध तरीके से बिक्री कर रहे हैं। इससे न केवल सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि आम नागरिक और किसान भी ठगी का शिकार हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायतें दी गई, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। लखनऊ जिला अध्यक्ष राजू रावत के नेतृत्व में आयोजित होने वाले इस प्रदर्शन में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से किसान प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। संगठन का कहना है कि यह आंदोलन किसानों के अधिकारों की रक्षा और भूमि घोटालों के खिलाफ जनजागरण का अभियान है। नव भारतीय किसान संगठन परिवार ने सभी किसान भाइयों से अपील की है कि वे 29 जून 2026 को लखनऊ के डालीगंज पुल के पास निर्धारित स्थल पर समय से पहुंचकर आंदोलन को सफल बनाएं। संगठन का मानना है कि किसानों और आम जनता के हितों की रक्षा के लिए भूमि से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और कठोर कार्रवाई आवश्यक है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि भूमाफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

## नशेड़ी बेटे ने पीट-पीटकर पिता की हत्या

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**लालगंज (रायबरेली)।** कोतवाली क्षेत्र के रामनगर टिकरान गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां नशे के आदी बताए जा रहे एक युवक ने अपने 60 वर्षीय पिता की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव निवासी देवतादीन और उनके बेटे दिलीप के बीच रविवार देर रात किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि विवाद के दौरान दिलीप ने पिता के साथ मारपीट की। ग्रामीणों के अनुसार आरोपी युवक नशे का आदी है। परिजनों का कहना है कि सोमवार सुबह भी दिलीप ने पिता की बेरहमी से पिटाई की। गंभीर रूप से घायल देवतादीन घर के पास बने छप्पर के नीचे पड़े रहे। कुछ समय बाद परिजनों ने उन्हें देखा तो उनकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही गांव में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के बेटे सोनू ने बताया कि पिता भी नशे के आदी थे और परिवार में अक्सर विवाद होता रहता था। एक सप्ताह पहले विवाद के बाद उनकी मां कृष्णा कुमारी घर छोड़कर चली गई थीं, जिनका अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। परिजनों के मुताबिक दिलीप गुजरात में मजदूरी करता है और दो दिन पहले ही गांव लौटा था। रुपये के लेनदेन को लेकर पिता-पुत्र के बीच विवाद चल रहा था। रविवार रात झगड़े के बाद दिलीप रिश्तेदारी में चला गया था और सोमवार सुबह लौटकर उसने फिर पिता के साथ मारपीट की। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। मृतक के बेटे सुशील, सुनील, सोनू और बेटियां पिंकी, रिंकी व प्रियंका का रो-रोकर बुरा हाल है। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

### अधिवक्ताओं का आंदोलन जारी न्यायिक कार्य से विरत रहे अधिवक्ता

**लालगंज (रायबरेली)।** बैसवारा अधिवक्ता एसोसिएशन और बेंच के बीच चल रहा गतिरोध सोमवार को भी जारी रहा। अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया और न्यायिक कार्य से विरत रहे। इस दौरान अधिवक्ताओं ने नारेबाजी कर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। धरने का नेतृत्व एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र नाथ सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि तहसील में विभिन्न स्तरों पर अनियमितताएं व्याप्त हैं। अधिवक्ताओं की समस्याओं और शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। संगठन अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. विनय भदौरिया ने कहा कि पीठासीन अधिकारियों का रवैया अधिवक्ताओं के प्रति उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रदेश स्तर पर पारित प्रस्ताव के तहत एक जून से 30 जून तक अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत हैं। इसके बावजूद कई मामलों में एकपक्षीय सुनवाई कर निर्णय दिए जा रहे हैं। धरना प्रदर्शन में वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेश त्रिवेदी, दल बहादुर, सीबी सिंह, राजबहादुर मौर्य, शिवानी सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।

### समाजवादी पार्टी कार्यालय उद्घाटन समारोह में उमड़ा जनसैलाब

**बिसवां-** विधानसभा क्षेत्र (149) में समाजवादी पार्टी कार्यालय का भव्य उद्घाटन पूर्व राज्य मंत्री कमलेश कुमार यादव जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस अवसर पर क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों की उत्साहपूर्ण उपस्थिति ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया। कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जयकरन यादव जी, उदय भान राजवंशी जी, मेहराज चौधरी जी, प्रमोद शुक्ला जी, अनिल यादव जी, राम दुलारे यादव जी, मुलायम यादव जी, सत्रोहन यादव जी, हनीफ नेता जी, शालीम जी, डॉ. जाहिद जी, राकेश यादव जी, देवेंद्र यादव जी, उपेंद्र वर्मा जी, पिंटू यादव जी, अवधेश गौतम जी, धर्मेंद्र यादव जी सहित अनेक सम्मानित नेताओं, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने सहभागिता कर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। यह विशाल जनसमर्थन समाजवादी विचारधारा के प्रति जनता के अटूट विश्वास एवं 2027 के परिवर्तन संकल्प का प्रतीक है।

## पंजाब राज्य को कर्ज मुक्त बनाने के लिए राजनीतिक दल आगे आएं : महंत मनोज शर्मा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**चंडीगढ़-** समाजसेवी एवं हिंदू चिंतक महंत मनोज शर्मा ने पंजाब की भलाई का दावा करने वाली सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील करते हुए कहा है कि यदि वे वास्तव में पंजाब के विकास और भविष्य को लेकर गंभीर हैं, तो सबसे पहले राज्य को कर्ज के बोझ से मुक्त करने के लिए ठोस कदम उठाएं।महंत मनोज शर्मा ने अपने बयान में कहा कि पंजाब आज भारी कर्ज के दबाव से जूझ रहा है, जिसका असर राज्य के विकास कार्यों, रोजगार के अवसरों और आम जनता के जीवन पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दल करोड़ों रुपये प्रचार और अन्य गतिविधियों पर खर्च करते हैं, जबकि वही धनराशि यदि राज्य के हित में लगाई जाए तो पंजाब को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सकता है।उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि चुनावों में अनावश्यक धन खर्च करने के बजाय अपने-अपने फंड से पंजाब का कर्ज उतारने में योगदान दें। उनका कहना था कि जनता के हितों की बात करने वाले दलों को पहले राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आगे आना चाहिए।महंत मनोज शर्मा ने कहा कि पंजाब की खुशहाली, विकास और आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए कर्जमुक्त पंजाब का सपना साकार करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राजनीतिक दल इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए राज्यहित में सकारात्मक पहल करेंगे।

## प्रधानमंत्री आवास योजना की अंतिम पात्रता सूची में से नाम कटने से ग्रामीणों का फूटा गुस्सा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**महराजगंज/रायबरेली:** प्रदेश सरकार जहां एक ओर ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह माह बढ़ाकर उन्हें बड़ी सौगात देने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री आवास योजना की अंतिम पात्रता सूची में बड़ी संख्या में नाम कटने से ग्रामीण क्षेत्रों में असंतोष गहराता जा रहा है। ताजा मामला महराजगंज विकासखंड की ग्राम पंचायत जमुरावां का है, जहां सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना की अंतिम सूची जारी होने के बाद सैकड़ों ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आपको बता दें कि, आक्रोशित ग्रामीण पंचायत भवन पहुंच गए और ग्राम प्रधान की गैरमौजूदगी में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पंचायत भवन परिसर में आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि, आखिर ग्राम सभा से फीड किए गए सैकड़ों पात्र लोगों के नाम अंतिम सूची से किसके निर्देश पर हटाए गए और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ग्रामीणों के अनुसार, 7 अप्रैल तक प्रकाशित प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची में ग्राम सभा जमुरावां के 359 लोगों के नाम दर्ज थे, लेकिन शासन द्वारा जारी अंतिम सूची में केवल 165 लाभार्थियों के नाम ही शामिल किए गए हैं। इससे 194 पात्र लोगों के नाम सूची से गायब हो गए हैं, जिससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी व्याप्त है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना था कि, जिन लोगों को आवास मिलने की उम्मीद थी, वे अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कई परिवार ऐसे हैं जो कच्चे और जर्जर मकानों में जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम अंतिम सूची से हटा दिया गया है। ग्रामीणों ने मांग करी कि, सूची में नाम कटने की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और पात्र लाभार्थियों को उनका हक दिलाया जाए। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि, यदि नाम हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है तो प्रशासन यह सार्वजनिक करे कि, किन मानकों के आधार पर इतने बड़े पैमाने पर नामों को सूची से बाहर किया गया। उनका कहना था कि, गरीबों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की अंतिम पात्रता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। यदि किसी ग्राम सभा के ग्रामीणों को सूची को लेकर कोई आपत्ति है तो वे संबंधित विकासखंड कार्यालय में जाकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि, प्राप्त शिकायतों की जांच कर नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा। गौरतलब है कि, महराजगंज विकासखंड की 53 ग्राम पंचायतों में केवल जमुरावां ही ऐसी पंचायत नहीं है जहां प्रधानमंत्री आवास योजना की अंतिम सूची को लेकर विवाद खड़ा हुआ हो। क्षेत्र की कई अन्य ग्राम पंचायतों में भी बड़ी संख्या में पात्र लोगों के नाम अंतिम सूची से गायब होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इससे योजना की पारदर्शिता और पात्रता निर्धारण की प्रक्रिया पर सवाल खड़े होने लगे हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि, यदि समय रहते प्रशासन ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया तो आंदोलन और तेज हो सकता है। अब सबकी निगाहें प्रशासनिक जांच और शासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं कि, आखिर गरीबों के सपनों के आशियाने की सूची से सैकड़ों नाम कैसे और क्यों गायब हो गए।

## संक्षिप्त खबरें

### डॉक्टर ने वेब सीरीज 'Raakh' के स्टाइल में जमा कर रखे थे चाकू और तलवार, दिल्ली मेड मर्डर केस में चौंकाने वाले खुलासे

**नई दिल्ली।** दक्षिण दिल्ली के माउंट कैलाश में डॉक्टर द्वारा अपनी 15 साल से काम कर रही घरेलू नौकरानी का गला रेतकर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस को चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी डॉक्टर मनीष गुप्ता ने वेब सीरीज 'राख' की तर्ज पर सालों से घर में चाकू, तलवार और खुकरी का बड़ा संग्रह जमा कर रखा था। पुलिस जांच में पता चला कि हत्या में इस्तेमाल की गई खुकरी भी इन्हीं स्मृति चिन्हों में से एक थी, जिसे डॉक्टर ने देश के विभिन्न राज्यों से इकट्ठा किया था। पुलिस के अनुसार, 19 जून को डॉ. मनीष गुप्ता (50) ने अपनी घरेलू सहायिका मीना (45) पर हमला किया। उन्होंने पहले अपने बेटे का क्रिकेट बैट लेकर मीना पर बार-बार हमला किया, फिर खुकरी से उनका गला रेत दिया। मीना का शव छत पर पड़ा मिला। पुलिस ने डॉ. गुप्ता के घर से वह खुकरी बरामद कर ली है, जिससे हत्या की गई। यह खुकरी उनके संग्रह की थी, जिसमें उन्होंने वर्षों में देश के विभिन्न राज्यों से ऐसी कई खुकरियां जमा की थीं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मीना की गर्दन पर मिला घाव चिकित्सकीय चीरे जैसा था। मीना रोज की तरह काम पर आई थीं और कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई थीं। इसी दौरान डॉ. गुप्ता ने उन पर हमला कर दिया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो डॉ. गुप्ता घर के अंदर थे। उन्होंने पुलिस से कहा, 'मुझे फांसी दे दो।' जांच में पता चला है कि डॉ. मनीष गुप्ता पिछले करीब 10 साल से डिप्रेशन और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर (OCD) का इलाज करा रहे थे। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या उन्होंने अपनी दवाइयां बंद कर दी थीं।

### बारिश से पहले ही 'डूबने' को तैयार दिल्ली, नालों से निकली गाद उठाना भूला PWD

**नई दिल्ली।** दिल्ली में मानसून की दस्तक से पूर्व लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। बरसाती नालों की सफाई के नाम पर खानापूर्ति का आलम तो जारी है ही, नालों से निकाली गई गाद उठाने के मामले में भी विभाग के अधिकारी पिछले सालों की गलतियों से कोई सबक नहीं ले रहे हैं। मानसून को देखते हुए विभाग द्वारा यह स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे कि नालों से निकाली गई गाद को 24 घंटे के अंदर मौके से हटा लिया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत इन कागजी दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। राजधानी के कई इलाकों में नालों से निकाली गई गाद पांच से लेकर आठ दिनों तक सड़कों और नालियों के किनारे यूं ही पड़ी है। इस लापरवाही ने आम जनता की चिंताएं बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग द्वारा जताई जा रही तेज वर्षा की संभावनाओं के बीच यह आशंका प्रबल हो रही है कि यदि समय रहते इस गाद को नहीं उठाया गया, तो वर्षा का पानी इसे वापस नालों में बहा ले जाएगा। नालों के फिर से चोक होने की स्थिति में सड़कों पर भारी जलभराव का संकट पैदा हो सकता है। स्थानीय निवासियों और जागरूक नागरिकों का आरोप है कि विभाग के अधिकारी शायद इसी स्थिति का इंतजार कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि यदि पहली ही वर्षा में गाद वापस नाले में चली जाती है, तो अधिकारियों और ठेकेदारों को दोबारा गाद निकालने के नाम पर एक और भ्रष्टाचार का रास्ता मिल जाएगा।

# कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन को तुरंत खत्म करने का आदेश, दिल्ली पुलिस ने फाउंडर अभिजीत को भेजा नोटिस

**● दिल्ली के जंतर-मंतर पर तय समय के बाद जारी रहे प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने सख्ती दिखाई है. कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके को नोटिस भेजकर प्रदर्शन तुरंत खत्म करने का आदेश दिया गया है।**

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

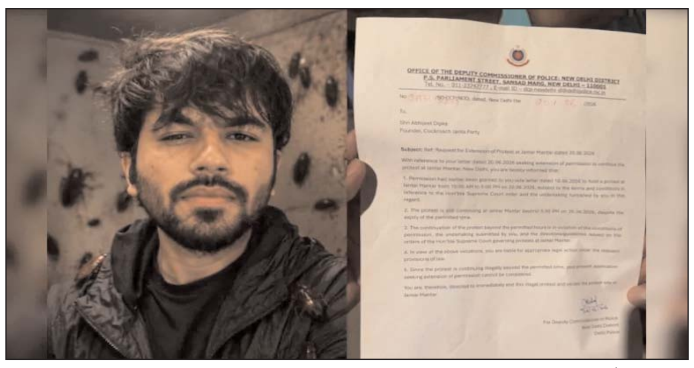

दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है. 'कॉकरोच जनता पार्टी' के प्रदर्शन को तय समय के बाद जारी रखने पर दिल्ली पुलिस ने तुरंत इसे खत्म करने का आदेश दे दिया है. पुलिस ने पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके को नोटिस भेजकर साफ चेतावनी दी है कि अब यह प्रदर्शन गैरकानूनी हो चुका है और अगर तुरंत नहीं रोका गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

**तय समय के बाद भी जारी रहा प्रदर्शन**

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक की ही अनुमति दी गई थी. लेकिन तय समय खत्म होने के बाद भी प्रदर्शन जारी रखा गया. इसे नियमों का सीधा उल्लंघन माना गया है।

**सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का हवाला**

पुलिस ने अपने नोटिस में कहा है कि तय समय के बाद प्रदर्शन करना सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों और पुलिस से ली गई परमिशन का उल्लंघन है. ऐसे में अब इस आंदोलन को जारी रखना अवैध माना जाएगा. दरअसल, कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से प्रदर्शन का समय बढ़ाने के लिए आवेदन दिया गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया. पुलिस का साफ कहना है कि नियमों में किसी तरह की ढील नहीं दी जा सकती।

**तुरंत जंतर-मंतर खाली करने के आदेश**

पुलिस ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रदर्शन तुरंत खत्म कर जंतर-मंतर खाली किया जाए. अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो आयोजकों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

### दिल्ली से सिखों का एक और जत्था पाकिस्तान पहुंचा, कार्यक्रम में होंगे शामिल

**नई दिल्ली।** महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली से 62 सदस्यीय श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान गया है। यह जत्था 29 जून को आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद 30 जून को भारत वापस लौटेगा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) द्वारा पिछले दिनों गुरु अर्जुन देव जी के बलिदान दिवस पर भी श्रद्धालुओं को पाकिस्तान भेजा गया था। डीएसजीएमसी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह काहलों ने कहा कि केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद श्रद्धालुओं को पाकिस्तान दूतावास से वीजा प्राप्त हुआ था। श्रद्धालु महाराजा रणजीत सिंह के पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही पाकिस्तान में स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन करेंगे। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु लाहौर में हुई थी। उन्होंने बताया कि डीएसजीएमसी की ओर से हर वर्ष बैसाखी और विभिन्न गुरुपर्वों के अवसर पर श्रद्धालुओं के जत्थे पाकिस्तान भेजे जाते हैं। इस बार 13 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद श्री अकाल तख्त साहिब के आदेशानुसार गुरु अर्जन देव जी का बलिदान दिवस देश-विदेश की संगतों द्वारा एक ही तिथि पर मनाया गया, जिससे पंथ में बनी हुई असमंजस की स्थिति समाप्त हुई है।

### राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद में अरविंद केजरीवाल की एंट्री, शुक्रवार को अयोध्या दौरे का किया एलान

**नई दिल्ली।** अयोध्या के श्रीरामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'अयोध्या श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी से हर सनातनी बेहद दुखी है। शुक्रवार को मैं दर्शन के लिये श्री राम मंदिर जाऊंगा।' बता दें कि राम मंदिर में करोड़ों रुपये के चढ़ावे और दान की कथित चोरी के मामले में हाल ही में सियासत तेज हो गई है। केजरीवाल ने पहले भी इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया था कि इतनी बड़ी चोरी होने के बावजूद अब तक एक भी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई। उन्होंने कहा था कि सरकार किसे बचा रही है?

### विधानसभा उतरी में 1.5 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 22 फुटा रोड का विधायक मदन लाल बग्गा ने किया उदघाटन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**लुधियाना-** लुधियाना विधानसभा उत्तरी में आरएमसी (रेडी मिक्स कंक्रीट) से बनने वाली 22 फुटा रोड के निर्माण कार्य का उदघाटन का शुभारंभ विधायक चौधरी मदन लाल बग्गा द्वारा किया गया। इस परौजाक्ट के निर्माण परक करीब 1.5 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस अवसर पर पार्षद पुष्पेन्द्र भनोट, पार्षद नरेन्द्र भारद्वाज, व गुरवीर गोलू बाजवा सहित स्थानीय निवासी तथा पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विधायक मदन लाल बग्गा ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए अपने विधायक कार्यकाल में हुए विकास कार्यो की जानकारी देते हुए कहा विधानसभा उतरी में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। पंजाब सरकार और स्थानीय प्रशासन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं। करीब डेढ़ करोड़ की लागत से बनने वाली 22 फुटा रोड के निर्माण से हजारों लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी तथा क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू होगी। बग्गा ने बताया कि आरएमसी सड़कें अधिक टिकाऊ और मजबूत होती हैं, जिससे लोगों को लंबे समय तक बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध होगी। पंजाब सरकार की तरफ से मुफ्त इलाज के लिए प्रति परिवार 10 लाख की योजना की सफलता का जिक्र करते हुए उन्होने कहा मावां धीयां योजना के तहत जल्दी हर एससी महिला के खाते में 1500 व जनरल वर्ग से संबधित महिलाओ के खाते में एक-एक हजार रुपये ट्रांस्फर होंगे।

# सब-इंस्पेक्टर को विजिलेंस ब्यूरो ने 20,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**चंडीगढ-** पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अपने अभियान के दौरान, पुलिस स्टेशन फिल्लौर, जिला जालंधर में तैनात सब-इंस्पेक्टर अमनदीप कौर को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। आज यहां यह जानकारी देते हुए, स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने बताया कि उक्त आरोपी को मोहल्ला चौधरीयां, फिल्लौर पुलिस स्टेशन, जिला जालंधर के निवासी की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसके बेटे को ड्रग्स के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और आरोपी SI ने उसे जमानत दिलाने और कम मात्रा में ड्रग्स के साथ मामला दर्ज करने और उसका मोबाइल फोन वापस करने में मदद करने के लिए 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। मजबूरी में, उसने पहले ही 1000 रुपये रिश्वत दे दी थी। शिकायत करने वाले ने रिश्वत की मांग के बारे में पूरी बातचीत रिकॉर्ड भी कर ली थी। गैर-कानूनी रिश्वत देने को तैयार न होने पर, शिकायत करने वाले ने विजिलेंस ब्यूरो रेंज जालंधर से संपर्क किया। उसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, विजिलेंस ब्यूरो टीम ने आरोपी SI को दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायत करने वाले से 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके पास से दागी नोट बरामद किए गए। इस संबंध में, आरोपी के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो पुलिस स्टेशन जालंधर में भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले की आगे की जांच चल रही है।

# चलती बस में लगी आग करीब 71 यात्रियों की सूझबूझ से बची जान

**● लुधियाना से गोंडा जा रही बस बिजा के पास जली, यात्रियों का सामान राख; ड्राइवर, खलासी और ब्रोकर हिरासत में**

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**लुधियाना/खन्ना-** लुधियाना के ढोलवाल स्थित डिवीजन नंबर-6 क्षेत्र से उत्तर प्रदेश के गोंडा के लिए रवाना हुई एक निजी बस रविवार दोपहर एक बड़े हादसे का शिकार हो गई। करीब 60 यात्रियों को लेकर जा रही बस खन्ना के नजदीक बिजा क्षेत्र में पहुंचते ही अचानक आग की लपटों में घिर गई। गनीमत रही कि ड्राइवर द्वारा बस सड़क किनारे रोकने और यात्रियों को तत्काल बाहर निकालने के कारण एक बड़ा जान-माल का नुकसान टल गया। जानकारी के अनुसार, बस रविवार सुबह करीब 11:30 बजे लुधियाना से गोंडा के लिए रवाना हुई थी। 12 बजे हुआ हादसा बस में लगभग 60 यात्री, दो ड्राइवर, एक खलासी और यात्रियों को बस में बैठाने वाला कथित ब्रोकर अरमान भी सवार था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस बिजा के पास पहुंची ही थी कि अचानक उसके पिछले हिस्से से आग का बड़ा गुबार निकला और देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया।

**इमरजेंसी खिड़कियों से बाहर निकाले गए यात्री**

आग लगने के बाद बस में अफरा-तफरी मच गई। यात्रियों की चीख-पुकार के बीच बस को सड़क किनारे रोका गया और मुख्य दरवाजे के साथ-साथ इमरजेंसी खिड़कियां खोलकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कुछ ही मिनटों में आग इतनी विकराल हो गई कि पूरी बस धू-धू कर जलने लगी।

**तीन दमकल गाड़ियों ने पाया आग पर काबू**

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। बस में रखे यात्रियों के कपड़े, नकदी, जरूरी दस्तावेज और अन्य सामान भी आग की भेंट चढ़ गए।

**सिलेंडर फटने जैसी तेज आवाज से दहशत**

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आग लगने के कुछ समय बाद बस के अंदर से जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। लोगों ने आशंका जताई कि बस में रखा कोई गैस सिलेंडर फट गया था। आग बुझने के बाद जले हुए गैस चूल्हे, घरेलू बर्तन और अन्य सामान भी दिखाई दिए।

**ड्राइवर, खलासी और ब्रोकर मौके से भागे, पुलिस ने दबोचा**

सूत्रों के अनुसार, आग लगने के बाद बस का एक ड्राइवर, खलासी और यात्रियों को बस में बैठाने वाला ब्रोकर अरमान मौके से फरार हो गया था। हालांकि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों को खन्ना स्थित शनि मंदिर के पास से हिरासत में ले लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है।

**जांच के घेरे में बस की फिटनेस और सुरक्षा व्यवस्था**

हादसे के बाद बस की फिटनेस, अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, यात्रियों की क्षमता से अधिक सामान ले जाने और सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस और संबंधित विभाग मामले की जांच में जुटे हुए हैं। प्रारंभिक जांच में आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए तकनीकी टीम की सहायता ली जा रही है।

## श्रीभूमि जिले के निविया निकट सोनापुर में एयरटेल नेटवर्क से परेशानी, दूरसंचार मंत्री के हस्तक्षेप

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**श्रीभूमि:** डिजिटल इंडिया के तहत देश के दूरदराज क्षेत्रों तक बेहतर दूरसंचार सेवाएं पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। 5जी, 4जी, 3जी और 2जी नेटवर्क के विस्तार के माध्यम से डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। हालांकि, जिले के निविया निकट स्थित सोनापुर गांव में इसकी विपरीत तस्वीर देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सोनापुर क्षेत्र में लंबे समय से एयरटेल का नेटवर्क अत्यंत कमजोर बना हुआ है। इसके कारण उपभोक्ताओं को नियमित रूप से फोन कॉल करने, कॉल प्राप्त करने और इंटरनेट उपयोग में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में यह समस्या लाई, लेकिन अब तक कोई प्रभावी समाधान नहीं किया गया है। ग्रामीणों के अनुसार, वर्तमान समय में बैंकिंग सेवाएं, कैशलेस लेनदेन, सरकारी दस्तावेजों का सत्यापन तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए मोबाइल नेटवर्क अनिवार्य हो गया है। लेकिन कमजोर नेटवर्क के कारण उन्हें इन सेवाओं का उपयोग करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इससे समय और धन दोनों की हानि हो रही है। स्थानीय उपभोक्ताओं का कहना है कि नेटवर्क समस्या के कारण कई बार आपातकालीन फोन कॉल भी पूरी नहीं हो पाती हैं। इसके अलावा ऑनलाइन सेवाओं, डिजिटल भुगतान और विभिन्न सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। लंबे समय से समस्या का स्थायी समाधान न होने के कारण ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इस स्थिति को

देखते हुए सोनापुर के निवासियों ने मामले की शीघ्र जांच कर आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय दूरसंचार मंत्री, जिला उपायुक्त (डीसी) तथा संबंधित अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि जल्द ही प्रभावी कदम उठाकर सोनापुर क्षेत्र में बेहतर और निर्बाध दूरसंचार सेवाएं सुनिश्चित होगी।

# अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का ओजयान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**लुधियाना-** इसमें विधायक राजिंदरपाल कौर छीना, कुलवंत सिंह सिद्धू, दलजीत सिंह ग्रेवाल, चौधरी मदनलाल बग्गा, मेयर इंद्रजीत कौर, पार्षद अमन बग्गा व डॉ.अंबेडकर वेलफेयर सोसायटी के प्रधान हसंराज ने विशेष रूप से शिरकत की। इस समारोह में जिला प्रशासन के सहयोग के वन विभाग, खेल विभाग, सीएम दी योगशाला व विभिन्न योग संस्थानों के 380 से अधिक योग साधकों व लोगों ने भाग लिया। विधायक ग्रेवाल ने सेहत को सबसे बड़ी पूंजी बताया। उन्होंने कहा कि युवा पीढी को नशों से दूर रखने के लिए योगा की अहम भूमिका बताई। विधायक राजिंदरपाल कौर छीना ने कहा कि योगाभ्यास से ओवरऑल हेल्थ में सुधार होता है। मेयर इंद्रजीत कौर ने कहा कि योग के माध्मय से तनाव व डिप्रेशन को भी दूर किया जा सकता है। इस मौके ड्रग्स मैन्यूफेक्चरिंग एसोसिएशन ने विधायक का सम्मान किया। इस मौके विधायक ने विभाग की डॉ.रुपिंदर कौर को सम्मानित किया, जो दुनिया की सबसे ऊंची एवरेस्ट चोटी के बस कैंप में पहुंचने वाली पहली भारतीय व्हील चेयर पोलियो सवाइवर हैं।

इस मौके नोडल अफसर डॉ.रजनी बाला, डॉ.हेमंत कुमार, डॉ.नवदीप, डॉ.नीरू कलसी ने झंडू, एमिल,नागार्जुन, देशावरी आदि व आयुव्रेदिक ड्रग मैन्यूफेक्चर एसोसिएशन लुधियाना, वन विभाग, जिला खेल विभाग व वेरका के अधिकारियों का आभार जताया। समारोह में मंच संचालन डॉ.शिवाली अरोड़ा व डॉ.राजन कौशल ने किया।

### दिल्ली के शेख सराय फेज-2 में अवैध निर्माण के दौरान भरभराकर गिरी दीवार, मची अफरा-तफरी

**दक्षिणी दिल्ली।** दिल्ली के शेख सराय फेज-2 में अवैध निर्माण के दौरान हादसे की खबर है। मालवीय नगर थाना क्षेत्र के शेख सराय फेज-दो स्थित पाकेट-के में मकान नंबर -101 में अवैध तरीके से मकान बनाते समय अचानक दीवार भरभराकर गिरी। हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

# फर्जी फर्मों के करंट अकाउंट से ठगी का बड़ा खेल; दिल्ली में अंतरराज्यीय साइबर गिरोह का भंड़ाफोड़, 4 गिरफ्तार

**● मध्य जिला पुलिस ने पहाड़गंज में एक अंतरराज्यीय साइबर ठगी सिंडिकेट का भंडाफोड़ कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह फर्जी बैंक खातों और पीओएस मशीनों के जरिए देशभर में साइबर अपराधियों को वित्तीय ढांचा मुहैया कराता था।**

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**नई दिल्ली।** साइबर अपराधियों को फर्जी बैंक खाते और पीओएस मशीनें आपूर्ति करने वाले एक अंतरराज्यीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ की मध्य जिला के साइबर सेल थाना पुलिस ने पहाड़गंज के एक होटल में छापेमारी कर गिरोह के चार गुर्गे को गिरफ्तार किया है। यह सिंडिकेट देशभर में साइबर ठगी करने वाले साइबर अपराधियों को बैंकिंग और अन्य वित्तीय बुनियादी ढांचा मुहैया करा रहा था। पुलिस ने इनके पास से एक्टिव पीओएस टर्मिनल, डेबिट कार्ड, साइन किए हुए ब्लैंक चेक बुक और कई डिजिटल दस्तावेज बरामद किए हैं। जांच में सामने आया है कि जब्त किए गए खाते कर्नाटक और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में हुए साइबर धोखाधड़ी से जुड़े हैं। डीसीपी, मध्य जिला, रोहित राजबीर सिंह का कहना है कि गिरफ्तार किए गए आरोपित पहाड़गंज के होटल से सिंडिकेट चला रहा था। एसीपी साइबर सेल और इंस्पेक्टर की टीम को सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने पहाड़गंज के 'कृष्णा होटल' में छापेमारी कर वहां ये चारों को दबोच लिया। वहां पर आरोपित साइबर अपराधियों को बेचने के लिए बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे थे, तभी चारों को दबोच लिया गया।

**इन साइबर जालसाजों को पुलिस ने पकड़ा**

गिरफ्तार किए गए आरोपितों के नाम संजय, कुलदीप गोले, निर्दोष बिदलान व दीपक बिश्नोई है। संजय, आनंद पर्वत का रहने वाला है। यह स्थानीय कोऑर्डिनेटर था, जो बाहरी राज्यों के सप्लायर्स से संपर्क बनाए रखता था। कुलदीप गोले, पटेल नगर का रहने वाला है। यह खातों की लेयरिंग (पैसा घुमाने) और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट का काम देखता था। निर्दोष बिदलान, गोहाना, सोनीपत का रहने वाला है। यह फर्जी फर्में बनाने और बैंकिंग किट का इंतजाम करने वाला अंतरराज्यीय सप्लायर है। दीपक बिश्नोई, हनुमानगढ़ (राजस्थान) का रहने वाला है। यह श्रीगंगानगर में पढ़ाई करने के साथ-साथ एक्टिव म्यूल-अकाउंट (किराए के खातों) की किट अरेंज करता था।

**फर्जी फर्म बनाकर खुलवाते थे करंट अकाउंट**

पूछताछ में से पता चला कि यह सिंडिकेट बेहद व्यवस्थित तरीके से काम कर रहा था। बाहरी राज्यों के आरोपित फर्जी रेंट एग्रीमेंट के जरिये 'एसजी एंटरप्राइजेस', 'जीएम एंटरप्राइजेस' और 'एचएम ट्रेडर्स' जैसी फर्जी पार्टनरशिप फर्में बनाते थे और उनके नाम पर कमर्शियल करंट अकाउंट खुलवाते थे। इन खातों की बैंकिंग किट, चेक बुक और दस्तावेज दिल्ली लाए जाते थे। ठगी की रकम को इन फर्जी खातों में डाला जाता था। इसके बाद पीओएस मशीन और मर्चेंट यूपीआई क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके उस अवैध पैसे को वैध बिजनेस ट्रांजेक्शन (वैध कमाई) की तरह दिखाया जाता था। खाता धारकों को करीब आठ प्रतिशत कमीशन दिया जाता था, जबकि एजेंट आपस में दो से चार प्रतिशत का अतिरिक्त कमीशन बांटते थे।

**मनी ट्रेल खंगाल रही है दिल्ली पुलिस**

पुलिस ने इनके कब्जे से एक एक्टिव इंडसइंड बैंक पीओएस टर्मिनल, एक मर्चेंट यूपीआई क्यूआर कोड स्कैनर, पांच कमर्शियल करंट अकाउंट की चेक बुक और पासबुक, छह एक्टिव एटीएम व डेबिट कार्ड, तीन असली पार्टनरशिप डीड और कॉरपोरेट दस्तावेज, कॉरपोरेट रबर स्टैम्प, पैन कार्ड और कमर्शियल रेंट एग्रीमेंट, चार मोबाइल फोन (बैंकिंग रिकार्ड और डिजिटल चैट से भरे हुए) बरामद किए गए

हैं। पुलिस अधिकारी का कहना है कि इन आरोपितों के तार राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल से जुड़े हुए हैं। तकनीकी जांच में सामने आया कि जब्त किए गए खाते पहले से देश के कई साइबर धोखाधड़ी से जुड़े हुए हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक खाता एनसीआरपी की शिकायत से लिंक्ड मिला है। इंडसइंड बैंक का खाता कर्नाटक और महाराष्ट्र के साइबर ठगी से जुड़ा पाया गया है। एक्सिस बैंक में 'लक्ष्मण एंटरप्राइजेस' के नाम पर खुला खाता पांच साइबर शिकायतों में दर्ज है। एचडीएफसी बैंक का एक खाता भी पांच अलग-अलग साइबर ठगी की शिकायतों में फ्लैग (चिह्नित) पाया गया। अदालत ने चारों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क के मनी ट्रेल (पैसे के लेन-देन के रास्ते) को खंगाल रही है ताकि पता लगाया जा सके कि इस सिंडिकेट से और कौन-से लोग जुड़े हैं और इन्होंने कितने करोड़ का ठगी की है।

## दिल्ली में फिर मंडराया बाढ़ का खतराः यमुना किनारे 50 करोड़ रुपये की दीवार का काम लटका

**● दिल्ली में यमुना के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ के खतरे को रोकने के लिए प्रस्तावित बाढ़रोधी दीवार का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। मानसून के बाद निर्माण शुरू होने की उम्मीद है।**

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**नई दिल्ली।** मानसून के दिनों में यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई क्षेत्रों में बाढ़ का पानी पहुंचने का खतरा रहता है। वर्ष 2023 में बाढ़ का पानी आवासीय क्षेत्रों में भरने से कई दिनों तक जनजीवन अस्तव्यस्त रहा था। पिछले वर्ष भी मजनू का टीला व बेला रोड क्षेत्र में पानी भर गया था। इसके समाधान के लिए मजनू का टीला से लेकर कश्मीरी गेट के नजदीक लोहा पुल तक रिंग रोड के किनारे बाढ़रोधी दीवार बनाया जाना है, लेकिन अभी तक इसका काम शुरू नहीं हो सका है। मानसून बाद निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। यानी इस वर्ष भी आवासीय क्षेत्रों में पानी भरने का खतरा बना रहेगा। दीवार की ऊंचाई लगभग 4.72 किलोमीटर होगी। इसमें से लगभग 850 मीटर अधिक संवेदनशील क्षेत्र में कंक्रीट की दीवार बनेगी। शेष हिस्से में ईंट या पत्थर की होगी। इसकी ऊंचाई लगभग छह फीट होगी। इसके निर्माण पर लगभग 50 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अधिकारियों का कहना है कि दीवार बनने से यमुना का पानी रिंग रोड व इसके पास के आवासीय क्षेत्र व बाजार में नहीं पहुंचेगा।

**अभी तक आवंटित नहीं हुआ काम**

मार्च में इसके निर्माण के लिए निविदा भी जारी कर दी गई थी। लेकिन, अभी तक किसी को काम आवंटित नहीं किया गया। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा का कहना

है कि पहले इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) माडल पर होना था निर्माण। इसमें निर्माण करने वाली एजेंसी भी डिजाइन बनाती है। ठेकेदारों द्वारा दिए गए डिजाइन में खामी थी। इस कारण सरकार ने आइआइटी दिल्ली को डिजाइन बनाने का काम दिया है। 10-15 दिनों में डिजाइन फाइनल होने की उम्मीद है। मानसून के बाद हो निर्माण कार्य शुरू होगा। बाढ़ का पानी आवासीय क्षेत्रों में नहीं पहुंचे इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।